RNI No. GUJHIN/2011/39228
GARVI GUJARAT
गरवी गुजरात
गरवी गुजरात
अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 16
अंक : 006
दि. 06.05.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

बंगाल में सियासी टकराव चरम पर, हार के बाद भी डटीं ममता बनर्जी-इस्तीफे से इनकार ने खड़ा किया संवैधानिक सवाल

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अभूतपूर्व घटनाक्रम सामने आया है, जहां विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी मुख्यमंत्री पद पर बनी रहने की बात कहकर ममता बनर्जी ने नया राजनीतिक और संवैधानिक विवाद खड़ा कर दिया है। उनके दो-टूक बयान—"न मैं लोकभवन जाऊंगी, न इस्तीफा दूंगी"—ने राज्य ही नहीं, बल्कि पूरे देश के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। यह स्थिति इसलिए भी असामान्य मानी जा रही है क्योंकि भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा में चुनावी हार के बाद मुख्यमंत्री द्वारा पद छोड़ना एक स्थापित मानक रहा है।

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने अपने रुख को केवल राजनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि नैतिक लड़ाई का रूप दिया है। उनका कहना है कि आधिकारिक परिणाम भले उनके खिलाफ गए हों, लेकिन नैतिक रूप से उनकी जीत हुई है। उन्होंने चुनाव परिणामों पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे "साजिश" करार दिया और आरोप लगाया कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रही। उनके मुताबिक, यह जनादेश का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि व्यवस्थित तरीके से उन्हें पराजित करने का प्रयास किया गया।

इस पूरे घटनाक्रम ने Election Commission of India की भूमिका पर भी बहस छेड़ दी है। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर आयोग पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया और इसे "बंगाल के इतिहास का काला अध्याय" बताया। उन्होंने यह भी दावा किया कि मतगणना के दौरान अनियमितताएं हुईं, उनके कार्यकर्ताओं को काउंटिंग सेंटर तक पहुंचने से

रोका गया और हिंसा की घटनाएं भी सामने आईं। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनके बयान ने राजनीतिक माहौल को और अधिक गरमा दिया है।

दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को केवल राज्य तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे राष्ट्रीय स्तर की लड़ाई का रूप देने का संकेत भी दिया है। उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन जैसे नेताओं ने उनसे संपर्क किया है और समर्थन जताया है। इससे यह संकेत मिल रहा है कि यह मुद्दा आगे चलकर विपक्षी एकता और राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

अपने बयान में ममता बनर्जी ने खुद को "आजाद पंछी" बताते हुए कहा कि अब उनके पास कोई कुर्सी नहीं है, इसलिए वह एक सामान्य नागरिक की तरह काम करेंगी। यह बयान अपने आप में विरोधाभासी प्रतीत होता है, क्योंकि एक ओर वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर खुद को पद से मुक्त बता रही हैं। यही विरोधाभास इस पूरे विवाद को और अधिक जटिल बना रहा है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देती हैं, तो संवैधानिक प्रक्रिया क्या होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और बहुमत खोने की स्थिति में उन्हें पद से हटाने का अधिकार भी राज्यपाल के पास होता है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के सामने कई विकल्प मौजूद हैं। वह पहले मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं, और यदि वह इनकार करती हैं, तो उन्हें बर्खास्त करने का निर्णय भी लिया जा सकता है।

एक अन्य संभावना यह भी है कि विधानसभा के कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही वर्तमान सरकार स्वतः समाप्त मानी जाए। चूंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को खत्म हो रहा है, इसलिए उसके बाद नई विधानसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं भी देती हैं, तो भी नई सरकार के गठन में कोई बाधा नहीं आएगी। राज्यपाल नई विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने भारतीय लोकतंत्र की परंपराओं और संवैधानिक मर्यादाओं पर भी बहस छेड़ दी है। अब तक यह माना जाता रहा है कि चुनावी हार के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद छोड़ना लोकतांत्रिक शिष्टाचार का हिस्सा है। लेकिन ममता बनर्जी के इस रुख ने इस परंपरा को चुनौती दी है और यह सवाल खड़ा किया है कि क्या भविष्य में अन्य नेता भी इसी रास्ते पर चल सकते हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल एक राज्य का मामला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह घटनाक्रम बताता है कि आने वाले समय में राजनीतिक संघर्ष केवल चुनावी मैदान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संवैधानिक और नैतिक विमर्श का भी हिस्सा बनेगा।

फिलहाल, बंगाल की राजनीति एक अनिश्चित मोड़ पर खड़ी है। एक ओर सत्ता, संविधान और परंपरा का सवाल है, तो दूसरी ओर राजनीतिक इच्छाशक्ति और संघर्ष का। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह टकराव किस दिशा में जाता है—क्या यह केवल एक राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर वास्तव में कोई संवैधानिक संकट खड़ा करेगा। इतना तय है कि ममता बनर्जी के इस फैसले ने भारतीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जिसका असर लंबे समय तक देखने को मिल सकता है।

तमिलनाडु में नया राजनीतिक समीकरण: विजय की पार्टी टीवीके बनी सबसे बड़ी ताकत, सरकार गठन को लेकर बढ़ी हलचल

चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में इस बार चुनावी नतीजों ने एक नया और अप्रत्याशित मोड़ ले लिया है। अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) राज्य में सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी है, हालांकि वह स्पष्ट बहुमत के आंकड़े से कुछ सीटें दूर रह गई है। इस स्थिति ने न केवल सरकार गठन की प्रक्रिया को जटिल बना दिया है, बल्कि तमिलनाडु की पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था में भी नई बहस छेड़ दी है।

चुनावी परिणामों के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और सभी प्रमुख दल अपनी-अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। टीवीके के इस अप्रत्याशित प्रदर्शन ने राज्य की राजनीति में युवा मतदाताओं की निर्णायक भूमिका को भी उजागर किया है। विश्लेषकों का मानना है कि इस बार का चुनाव केवल पारंपरिक दलों के बीच मुकाबला नहीं था, बल्कि यह एक नई राजनीतिक धारा के उभार का संकेत भी है।

नतीजों के बाद विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दी गई बधाई के लिए सार्वजनिक रूप से आभार व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि उनका एकमात्र लक्ष्य जनता का कल्याण है और राजनीति से ऊपर उठकर राज्य के विकास पर ध्यान देना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि केंद्र सरकार के साथ सहयोग की संभावना को वे सकारात्मक रूप से देखते हैं, ताकि राज्य के विकास कार्यों को गति दी जा सके।

विजय ने अपने संदेश में यह स्पष्ट किया कि उनकी राजनीति का केंद्र बिंदु तमिलनाडु की जनता का कल्याण, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और समग्र विकास है। उन्होंने कहा कि राजनीति से अधिक महत्वपूर्ण जनता की सेवा है और इसी दिशा में उनकी पार्टी आगे काम करेगी। उनके इस बयान को राजनीतिक हलकों में एक संतुलित और रणनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें टकराव की बजाय सहयोग का संकेत दिया गया है।

इस बीच, कांग्रेस की ओर से भी चुनाव परिणामों को लेकर समीक्षा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तमिलनाडु के प्रभारी गिरिश चोडणकर ने कहा है कि उन्होंने पूरे चुनावी परिदृश्य की विस्तृत रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में युवा और महिला मतदाताओं का बड़ा हिस्सा टीवीके की ओर झुका है, जिससे राजनीतिक समीकरणों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है।

कांग्रेस के अनुसार, यह चुनाव केवल सीटों का गणित नहीं था, बल्कि यह मतदाताओं की सोच में आए बदलाव का संकेत भी है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को पूरी स्थिति से अवगत कराया गया है और आगे की रणनीति अब केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा।

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि टीवीके का यह प्रदर्शन तमिलनाडु की पारंपरिक द्रविड़ राजनीति में एक नए युग की शुरुआत का संकेत हो सकता है। दशकों से राज्य की राजनीति मुख्य रूप से दो बड़े गठबंधनों के बीच घूमती रही है, लेकिन इस बार एक नए राजनीतिक खिलाड़ी का उभरना इस ढांचे को चुनौती देता नजर आ रहा है।

हालांकि, बहुमत से थोड़ा पीछे रह जाने के कारण सरकार गठन की प्रक्रिया अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। विभिन्न दलों के बीच संभावित गठबंधन, समर्थन और रणनीतिक समझौतों की चर्चा तेज हो गई है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि क्या टीवीके अकेले सरकार बनाने की स्थिति में आती है या फिर उसे अन्य दलों के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी।

इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखाया है कि तमिलनाडु की राजनीति अब एक संक्रमणकाल से गुजर रही है, जहां नए नेतृत्व, नई विचारधारा और नई राजनीतिक ऊर्जा का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। विजय के नेतृत्व में टीवीके का उभार इसी परिवर्तन का संकेत माना जा रहा है, जिसने राज्य की राजनीति को एक नई दिशा में मोड़ दिया है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में सत्ता की कुर्सी का समीकरण किस दिशा में जाता है और क्या यह नया राजनीतिक समीकरण राज्य में स्थिर सरकार की नींव रख पाएगा या फिर एक और राजनीतिक पुनर्गठन की शुरुआत करेगा।

बिना ट्रायल लंबी हिरासत मौलिक अधिकार का उल्लंघन सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, जमानत पर बड़ा आदेश

नई दिल्ली/कोल्हापुर। भारतीय न्याय व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्यायिक प्रक्रिया की गति को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है कि बिना निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई के किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रखना संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अदालत ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें निष्पक्ष और शीघ्र न्याय पाने का अधिकार भी शामिल है।

यह टिप्पणी एक हत्या के मामले में आरोपी साहिल मनोज मचारे को जमानत देते हुए की गई। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि आरोपी लगभग चार वर्षों से न्यायिक हिरासत में है, जबकि ट्रायल प्रक्रिया बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रही है।

अदालत के सामने यह तथ्य रखा गया कि आरोपी 1 नवंबर 2022 से जेल में बंद है और 2024 में आरोप तय होने के बावजूद अब तक एक भी गवाह का बयान दर्ज नहीं किया गया है। इस स्थिति को अदालत ने अत्यंत गंभीर माना और कहा कि यह न्यायिक प्रक्रिया की विफलता को दर्शाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी

भी आपराधिक मामले में गंभीरता के बावजूद, व्यक्ति को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखना स्वीकार्य नहीं है। यदि ट्रायल समय पर आगे नहीं बढ़ता है, तो अदालतों का कर्तव्य बनता है कि वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में निर्णय लें। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि त्वरित सुनवाई का अधिकार केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार है।

इस मामले में आरोपी ने पहले बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मार्च 2026 में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि केवल आरोप की गंभीरता के आधार पर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता।

मामला महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के शाहापुर थाने से जुड़ा है, जहां भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के तहत हत्या का केस दर्ज किया गया था। अभियोजन के अनुसार, तारदाल गांव में एक पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद में धारदार हथियार से हमला कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। एक प्रत्यक्षदर्शी ने आरोपी की पहचान सह-आरोपी के रूप में की थी।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह तय करना ट्रायल कोर्ट का काम है कि आरोपी दोषी है या नहीं, लेकिन जब तक सुनवाई अनिश्चितकाल तक लंबित रहती है, तब तक किसी व्यक्ति को जेल में रखना न्यायसंगत नहीं हो सकता। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि आरोपी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है, तो उसे आवश्यक शर्तों के साथ तुरंत रिहा किया जाए।

इस फैसले को न्यायिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में कई मामलों में ट्रायल की धीमी गति के कारण आरोपी वर्षों तक जेल में बंद रहते हैं, जिससे न्याय और स्वतंत्रता के बीच संतुलन प्रभावित होता है। यह निर्णय इसी असंतुलन को सुधारने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रुख से यह स्पष्ट कर दिया है कि न्याय केवल दोषसिद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रक्रिया की निष्पक्षता और समयबद्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यह फैसला न केवल इस विशेष मामले के लिए, बल्कि भविष्य में ऐसे सभी मामलों के लिए एक नजीर बन सकता है, जहां लंबी हिरासत और धीमी सुनवाई का मुद्दा सामने आता है।

इस आदेश के बाद कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रायल कोर्टों और जांच एजेंसियों पर यह दबाव बढ़ेगा कि वे मामलों की सुनवाई में तेजी लाएं, ताकि किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से लंबे समय तक जेल में न रहना पड़े।

कृत्रिम पनीर पर शिकंजा कसने की तैयारी उपभोक्ता सुरक्षा के लिए बड़ा कदम

नई दिल्ली। देश में खाद्य सुरक्षा को लेकर सरकार अब एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। बाजार में खुलेआम बिक रहे तथाकथित 'कृत्रिम पनीर' पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की तैयारी तेज हो गई है। यह फैसला उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से इस सस्ते लेकिन संदिग्ध उत्पाद को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इस दिशा में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि जल्द ही ऐसे उत्पादों को बाजार से चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा।

मामले से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, इस प्रस्ताव को पहले ही उच्चस्तरीय समिति द्वारा तैयार किया जा चुका है। अक्टूबर 2025 में इस पर प्रारंभिक सहमति बनी थी, जिसके बाद मार्च 2026 की बैठक में इसे औपचारिक मंजूरी भी दे दी गई। यह निर्णय ऐसे समय में आया है, जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी उत्पादक देश होने के बावजूद नकली या कम गुणवत्ता वाले डेयरी उत्पादों की चुनौती से जूझ रहा है। कृत्रिम पनीर, जो देखने और स्वाद में असली पनीर जैसा लगता है, उपभोक्ताओं को भ्रमित कर रहा है और उनकी सेहत के लिए जोखिम पैदा कर रहा है।

असल में यह 'कृत्रिम पनीर' दूध से नहीं, बल्कि पाम ऑयल, मिल्क पाउडर, स्टार्च और इमल्सीफायर्स जैसे तत्वों से तैयार किया जाता है। इसकी बनावट और रंग इस तरह बनाए जाते हैं कि आम ग्राहक इसे असली पनीर समझ बैठता है। यही वजह है कि होटल, ढाबों और छोटे रेस्टोरेंट्स में इसका उपयोग तेजी से बढ़ा है, क्योंकि यह सस्ता पड़ता है और मुनाफा बढ़ाता है। लेकिन इस सस्ते विकल्प की कीमत अंततः उपभोक्ता अपनी सेहत से चुका रहा है।

सरकार की योजना के तहत अब नए लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे और जिन कंपनियों के पास पहले से लाइसेंस है, उन्हें उत्पादन बंद करने और स्टॉक खत्म करने के लिए समय दिया जाएगा। फिलहाल देश में लगभग 1,000 ऐसे लाइसेंसधारी मौजूद हैं, जो इस तरह के उत्पाद का निर्माण या कारोबार कर रहे हैं। यह कदम अचानक बंदी के बजाय एक संतुलित संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है, ताकि उद्योग को भी समायोजन का समय मिल सके।

हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस प्रतिबंध का असर सोया पनीर यानी टोफू या नारियल आधारित उत्पादों पर नहीं पड़ेगा। ये उत्पाद पहले से ही निर्धारित मानकों के तहत बाजार में उपलब्ध हैं और इन्हें वैकल्पिक प्रोटीन स्रोत के रूप में मान्यता प्राप्त है। सरकार का उद्देश्य किसी वैध उत्पाद को रोकना नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाले नकली विकल्पों को हटाना है।

इस निर्णय के पीछे सबसे बड़ा कारण स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कृत्रिम पनीर में प्रोटीन की मात्रा बेहद कम होती है, जबकि इसमें वसा की मात्रा असामान्य रूप से अधिक हो सकती है। इसका नियमित सेवन शरीर में इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ा सकता है, जिससे टाइप-2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा, यह शरीर में सूजन को बढ़ावा देता है, जो हृदय रोग, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से जुड़ा हुआ है। कुछ मामलों में इसमें ऐसे रसायनों के उपयोग की आशंका भी जताई गई है, जो लिवर और किडनी के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

आर्थिक दृष्टि से भी यह मुद्दा महत्वपूर्ण है। असली ब्रांडेड पनीर की कीमत जहां लगभग 450 रुपये प्रति किलो तक होती है, वहीं कृत्रिम या बिना ब्रांड वाला पनीर 250 से 300 रुपये प्रति किलो तक आसानी से मिल जाता है। यह बड़ा अंतर कई विक्रेताओं को सस्ते उत्पाद को असली बताकर बेचने के लिए प्रेरित करता है। इससे न केवल उपभोक्ता ठगे जाते हैं, बल्कि असली डेयरी उद्योग को भी नुकसान होता है।

भारत में पनीर केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं, बल्कि आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर उत्तर भारत में। यहां इसे प्रोटीन के प्रमुख स्रोत के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि देश का पनीर बाजार तेजी से बढ़ रहा है और इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। मार्केट रिसर्च के अनुसार, आने वाले वर्षों में यह बाजार दोगुना होने की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में गुणवत्ता और शुद्धता बनाए रखना और भी जरूरी हो जाता है।

सरकार का यह कदम केवल एक उत्पाद पर प्रतिबंध नहीं, बल्कि एक व्यापक संदेश भी है—कि खाद्य सुरक्षा के मामले में अब कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि उन्हें जो भी उत्पाद मिले, वह सुरक्षित, शुद्ध और सही जानकारी के साथ हो। इस दिशा में उठाया गया यह कदम न केवल उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ाएगा, बल्कि डेयरी उद्योग को भी अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बनाएगा।

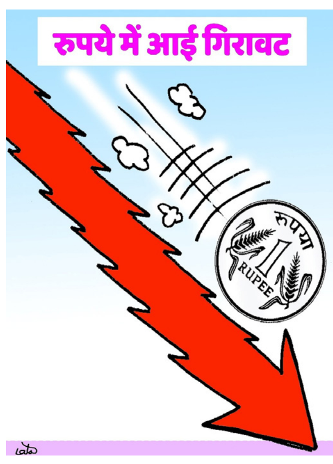

संपादकीय

दक्षता घटाती कोचिंग

पिछले दिनों आईआईटी खड़गपुर के डायरेक्टर प्रो. सुमन चक्रवर्ती के उस बयान ने चौंकाया कि कोचिंग के कारोबार ने छात्रों की सोचने की क्षमता को घटाया है। वे प्रतिभा विस्तार व मौलिक सोच में विकास के बजाय कोचिंग उद्योग के चतुराई के खेल में शामिल हो रहे हैं। वे दिमाग के इस्तेमाल के बजाय जेईई प्रवेश परीक्षा के लिए ट्रिक्स से गलत ऑप्शन हटाना सीख रहे हैं। फलतः वे आईआईटी जैसे उच्च संस्थानों में प्रवेश तो पा जाते हैं, लेकिन गुणवत्ता की शिक्षा से साम्य बैठाने में असफल साबित होते हैं, जिससे उनकी आईआईटी में बैक लगने यानी कुछ विषयों अनुतीर्ण होने से बैक लगने की स्थिति पैदा हो रही है। जिससे वे अक्सर तनाव में आ जाते हैं। हो सकता आने वाले समय में किसी अध्ययन व शोध से यह बात सामने आए कि उच्च तकनीक संस्थानों में बढ़ती आत्मघात की प्रवत्ति के पीछे कोचिंग संस्थानों की भेड़चाल से उपजी विसंगतियां हों। निश्चय ही यह स्थिति भारतीय उच्च व तकनीकी संस्थानों में विकसित हो रही इस नकारात्मक प्रवृत्ति को बढ़ाने वाली है। एक समय था कि भारतीय प्रतियोगिता परीक्षाओं की प्रणाली में स्वस्थ स्पर्धा हुआ करती थी। प्रतिभावान विद्यार्थी ही उच्च तकनीकी संस्थानों में प्रवेश पा सकते थे। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बाजार के लगातार बढ़ते दखल ने सारी स्थिति ही उलट कर रख दी। वहीं दूसरी ओर सीबीएसई और अन्य शिक्षा बोर्डों द्वारा सौ फीसदी तक अंक दिए जाने ने राज्यों के बोर्डों से परीक्षा उतीर्ण करने वाले छात्रों को हीन भावना से भर दिया। निस्संदेदह, वह शिक्षा प्रणाली सवालों के दायरे में आनी चाहिए, जिसमें असंभव से लगने वाले सौ फीसदी अंक छात्रों को दिए जाते हैं। सौ फीसदी अंक एक नहीं कई-कई छात्रों को दिए जाते हैं। वहीं राज्यों के विभिन्न बोर्डों में परीक्षक कंजूसी से नंबर देकर पहले ही छात्रों को राष्ट्रीय स्पर्धा से बाहर कर देते हैं। निश्चय ही यह स्थिति देश के लाखों छात्रों के साथ अन्याय जैसी है।

दरअसल, देश में पहले भी कोचिंग व्यवस्था मौजूद रही है। लेकिन एक सहायक की भूमिका में। आज कोचिंग कारोबारियों द्वारा उसे छात्रों के भविष्य का निर्धारण करने वाले एकमात्र विकल्प के रूप में बताया जा रहा है। यह व्यवस्था देश में व्याप्त आर्थिक विभेद को भी और बढ़ाती है। तय है कि संपन्न घरों से आने वाले बच्चे महंगी कोचिंग पाकर गुदड़ी के लालों के जीवन पर सदैव भारी पड़ेंगे। फलतः कुछ मध्यमवर्गीय परिवारों के अभिभावक बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए कर्ज लेकर कोचिंग का जुगाड़ करते हैं। अपना पेट काटकर वे बच्चों को महंगे कोचिंग संस्थानों में भेजते हैं। कई अभिभावक अक्सर कर्ज में डूब जाते हैं। वहीं शैक्षिक गुणवत्ता के नजरिये से देखें तो पहले जब कोचिंग एक सहायक की भूमिका में थी तो छात्र विस्तृत पढ़ाई से विषय को समझने का प्रयास करते थे। अब पूरी व्यवस्था कोचिंग केंद्रित होने से शिक्षा की व्यापकता खत्म हो रही है। इसका नकारात्मक प्रभाव यह है कि छात्र परीक्षा के तीन घंटों में सवाल समझकर हल करने की बजाय गलत विकल्पों को हटाने की कोचिंग्स द्वारा सिखायी ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। दरअसल, कोचिंग संस्थानों के तौर-तरीकों से छात्रों को 'स्पून फीडिंग' की लत लग जाती है। वहां हिंदी में पढ़ाई होती है और तैयार नोट्स को बार-बार रटाया जाता है। वहीं विडंबना यह है कि आईआईटी आदि उच्च तकनीकी संस्थानों में पढ़ाई अंग्रेजी में होती है। वहां समेस्टर सिस्टम में पढ़ाई सेल्फ-स्टडी पर आधारित होती है। यही वजह है कि महज ट्रिक्स द्वारा आईआईटी में प्रवेश करने वाले छात्र आगे की पढ़ाई के साथ साम्य नहीं बैठा पाते। उनको कई विषयों में पूरक परीक्षा देनी पड़ती है, जिससे सुनहरे सपने लेकर आए छात्र गहरे तनाव में आ जाते हैं। कई जगह होने वाले आत्मघात के पीछे यह कारण भी हो सकता है। वहीं टॉपर छात्रों को मीडिया तथा सोशल मीडिया में कोचिंग संस्थानों व अभिभावकों द्वारा सेलिब्रिटी की तरह पेश किया जाता है, जिससे वे इस ग्लैमर से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। वहीं परिवार का दबाव भी तनाव बढ़ाता है। इस गंभीर स्थिति का समाधान नीति-नियंताओं का करना चाहिए।

पश्चिम बंगाल में भाजपा की चली सुनामी के सियासी मायने दूरगामी महत्व वाले

> पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत केवल सरकार बदलने की घटना नहीं होगी, बल्कि यह भारतीय राजनीति में "पूर्वी भारत के वैचारिक परिवर्तन" का प्रतीक मानी जाएगी। इससे विपक्ष का शक्ति-संतुलन बदलेगा, भाजपा का राष्ट्रीय आत्मविश्वास बढ़ेगा और बंगाल की दशकों पुरानी राजनीतिक संस्कृति में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकता है।

केंद्र में विगत बारह वर्षों से सत्तारूढ़ 'भारतीय जनता पार्टी' ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में निर्णायक जीत दर्ज करके जनसंघ के संस्थापक और बंगाल मूल के दूरदर्शी हिंदूवादी राजनेता पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अद्भुत श्रद्धांजलि दी है। सच कहूं तो आरएसएस के इस सुप्रसिद्ध सिपाही का कश्मीर में दिया हुआ सियासी बलिदान व्यर्थ नहीं गया। खासकर यह उपलब्धि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर भाजपा द्वारा उसे दिया हुआ बहुमूल्य वैचारिक तोहफा है।पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत केवल सरकार बदलने की घटना नहीं होगी, बल्कि यह भारतीय राजनीति में "पूर्वी भारत के वैचारिक परिवर्तन" का प्रतीक मानी जाएगी। इससे विपक्ष का शक्ति-संतुलन बदलेगा, भाजपा का राष्ट्रीय आत्मविश्वास बढ़ेगा और बंगाल की दशकों पुरानी राजनीतिक संस्कृति में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकता है। कम शब्दों में कहा जाए तो भय हारा और भरोसा जीता है। भद्रलोक के हृदय परिवर्तन से सोनार बंगला के बहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिलने से हिंदुओं का मनोबल बढ़ेगा और बंगलादेशी घुसपैठियों से देश को मुक्ति मिलेगी। इस शुभ घड़ी को दिखलाने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति, भाजपा के राष्ट्रीय अध्ययन नितिन नवीन की सूझबूझ और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सियासी तेवरों का भी अहम योगदान है। वहीं, हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेताओं उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व सरमा के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं, पश्चिम बंगाल के राजनेता सुवेन्दु अधिकारी, दिलीप बोस जैसे कर्मठ नेताओं और भाजपा के 'बलिदानी' कार्यकर्ताओं के अथक संघर्ष का प्रतिफल है।

देखा जाए तो यह भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं और उनका हौसलाअफजाई करते रहने वाले स्थानीय और बाहरी नेताओं के संयुक्त प्रयासों का सकारात्मक नतीजा है, जिसके लिए वे सभी बधाई के पात्र हैं। बंगलादेश की हिन्दू विरोधी मानसिकता और ग्रेटर बंगलादेश की थ्योरी ने पूर्वी भारत के हिंदुओं

को इस कदर भयभीत कर दिया है कि अब उनके पास भाजपा के नेतृत्व में गोलबंद होने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। लिहाजा, पहले कलिंग यानी उड़ीसा, फिर अंग यानी बिहार और अब बंग यानी पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत और भगवा की बुलंदी बहुत कुछ राजनीतिक चुगली करती है, जिसे समझने, और जनमानस को समझाने की जरूरत है। दिल्ली एनसीआर में बसे पूर्वी भारत के कर्तव्यनिष्ठ आरएसएस/भाजपा नेताओं-कार्यकर्ताओं की मानें तो यह उनके सामूहिक प्रयासों की विजय हैजो अनवरत रूप से जारी अथक जनसंघर्षों और कार्यकर्ताओं के बलिदानों की वजह से मिली है। लिहाजा इसके राजनीतिक निहितार्थ केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति, संघीय ढांचे और विपक्ष की रणनीति पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। वहीं, निकट भविष्य में पूर्वी एवं पश्चिमी एशिया तक में इसकी अनुगूंज सुनाई पड़ेगी।

लिहाजा, इस अभूतपूर्व विजय के प्रमुख राजनीतिक निहितार्थ/मायने इस प्रकार होंगे

1. पूर्वी भारत में भाजपा का निर्णायक विस्तार

पश्चिम बंगाल लंबे समय तक वामपंथ और बाद में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहां भाजपा की जीत यह संकेत देगी कि पार्टी अब हिंदी पट्टी से आगे निकलकर पूर्वी भारत में स्थायी राजनीतिक शक्ति बन चुकी है। इससे ओडिशा, असम और पूर्वोत्तर में भाजपा की पकड़ और मजबूत होगी। अन्य राज्यों में विस्तार भी होगा।

2. ममता बनर्जी की राष्ट्रीय भूमिका कमजोर पड़ना

ममता बनर्जी विपक्षी राजनीति की सबसे आक्रामक नेताओं में मानी जाती रही हैं। बंगाल में हार होने पर उनकी "राष्ट्रीय विकल्प" वाली छवि को गहरा झटका लगेगा। इंडिया गठबंधन की राजनीति में उनका प्रभाव कम हो सकता है और विपक्ष का नेतृत्व पुनः बिखर सकता है। जबकि राहुल गांधी को मजबूती मिलेगी, क्योंकि उनकी टांग खींचने वाले सारे क्षेत्रीय नेता उनकी सटीक रणनीति से सियासी धूल फांकने को अभिशप्त हुए। इससे भविष्य में कांग्रेस लाभान्वित होगी।

3. कांग्रेस और वामपंथ का लगभग राजनीतिक अंत

पश्चिम बंगाल में पहले ही चुनाव भाजपा बनाम तृणमूल तक सिमटता दिख रहा है। भाजपा की जीत होने पर यह संदेश जाएगा कि कांग्रेस और वामदलों की पारंपरिक राजनीति बंगाल में अप्रासंगिक हो चुकी है।

4. "हिंदुत्व और कल्याणकारी राजनीति" मॉडल की सफलता

भाजपा ने बंगाल में राष्ट्रवाद, सीमा सुरक्षा, घुसपैठ, नागरिकता और हिंदू पहचान के मुद्दों को कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़कर चुनावी रणनीति बनाई है। यदि यह सफल होती है, तो पार्टी इस मॉडल को अन्य राज्यों में भी और आक्रामक रूप से लागू करेगी।

5. बंगाल की राजनीतिक संस्कृति में बड़ा बदलाव

बंगाल लंबे समय तक वैचारिक राजनीति, वामपंथी विमर्श और क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति के लिए जाना जाता रहा है। भाजपा की जीत यह संकेत देगी कि बंगाल की राजनीति अब वैचारिक संघर्ष से निकलकर राष्ट्रीय ध्रुवीकरण और पहचान-आधारित राजनीति की ओर बढ़ रही है।

6. 2029 लोकसभा चुनाव की दिशा तय होगी

भाजपा द्वारा बंगाल जीत से 2029 लोकसभा चुनाव के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त होगी। बंगाल की 42 लोकसभा सीटें राष्ट्रीय सत्ता संतुलन में बेहद महत्वपूर्ण हैं। भाजपा यह संदेश दे सकेगी कि उसका विस्तार अब दक्षिण और पूर्व भारत तक स्थायी रूप से हो चुका है।

7. संघ और भाजपा संगठन की रणनीति को वैधता

पश्चिम बंगाल में भाजपा का संगठन वर्षों तक कमजोर माना जाता था। यदि पार्टी सत्ता तक पहुंचती है, तो यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के दीर्घकालिक कैडर विस्तार मॉडल की बड़ी सफलता मानी जाएगी। सोशल और वैचारिक स्तर पर संघ की पैठ को भी मजबूती मिलेगी।

8. केंद्र-राज्य संबंधों में नया समीकरण

अब तक बंगाल और केंद्र सरकार के संबंध अक्सर टकरावपूर्ण रहे हैं। भाजपा सरकार बनने पर केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बढ़ेगा, जिससे निवेश, बुनियादी ढांचे और केंद्रीय परियोजनाओं को गति मिल सकती है। हालांकि विपक्ष इसे "संघीय ढांचे के केंद्रीकरण" के रूप में भी प्रस्तुत कर सकता है।

9. पहचान और सुरक्षा राजनीति को बल

सीमा पार घुसपैठ, एनआरसी-सीएए, बांग्लादेश सीमा और जनसांख्यिकीय बदलाव जैसे मुद्दे बंगाल की राजनीति के केंद्र में आ जाएंगे। भाजपा की जीत इन मुद्दों को राष्ट्रीय बहस में और प्रमुख बना सकती है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत केवल सरकार बदलने की घटना नहीं होगी, बल्कि यह भारतीय राजनीति में "पूर्वी भारत के वैचारिक परिवर्तन" का प्रतीक मानी जाएगी।

प्रेरणा

कला का धर्म और सृजन की अडिग आस्था

जब भी कला और बाजार के बीच टकराव होता है, तब असली परीक्षा कलाकार की होती है। एक ओर वह रास्ता होता है जो तुरंत लोकप्रियता और आर्थिक सफलता दिला सकता है, और दूसरी ओर वह पथ होता है जो कठिन, अनिश्चित, लेकिन सच्चा होता है। इतिहास गवाह है कि जो कलाकार इस कठिन रास्ते को चुनते हैं, वही अंततः अमर हो जाते हैं। ऐसी ही एक प्रेरक घटना जुड़ी है शैलेंद्र से, जिन्होंने अपनी फिल्म तीसरी कसम के माध्यम से यह साबित किया कि सच्ची कला किसी भी प्रकार के समझौते से परे होती है।

यह कहानी केवल एक फिल्म की नहीं, बल्कि उस सोच की है, जो कला को लाभ-हानि के गणित से अलग रखती है। शैलेंद्र ने जब अपने मित्र और प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वरनाथ 'रेणु' की कहानी पर फिल्म बनाने का निर्णय लिया, तब उनके मन में केवल एक ही उद्देश्य था—उस कहानी के मूल भाव को पूरी ईमानदारी के साथ परदे पर उतारना। यह कोई आसान कार्य नहीं था, क्योंकि सिनेमा एक ऐसा माध्यम है, जहां हर निर्णय पर व्यावसायिक दबाव होता है। निर्माता, वितरक और दर्शक—सभी की अपेक्षाएं अलग-अलग होती हैं, और इन सबके बीच संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है। जब फिल्म पूरी होकर तैयार हुई और उसे वितरकों को दिखाया गया, तब उनकी प्रतिक्रिया वही थी, जो अक्सर बाजार की दृष्टि से देखने वाले लोगों की होती है। उन्होंने सुझाव दिया कि फिल्म का अंत बदल दिया जाए, क्योंकि वर्तमान अंत दर्शकों को निराश कर सकता है। उनके अनुसार, यदि अंत को थोड़ा सकारात्मक और 'मनोरंजक' बनाया जाए, तो फिल्म की सफलता की संभावना बढ़ सकती है। यह सुझाव सुनने में भले ही व्यावहारिक लगे, लेकिन इसके पीछे कला की आत्मा को बदलने का खतरा छिपा हुआ था।

उस क्षण शैलेंद्र के सामने एक कठिन निर्णय था। वे चाहें तो वितरकों की बात मानकर फिल्म को अधिक व्यावसायिक बना सकते थे, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ भी हो सकता था और फिल्म को अधिक दर्शक भी मिल सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने भीतर की आवाज को सुना, जो उन्हें यह कह रही थी कि सच्ची कला को किसी भी प्रकार के दबाव में बदलना उसके साथ अन्याय है। उन्होंने अपने मित्र रेणु की ओर देखा, जिनकी आंखों में अपनी रचना के प्रति गहरी संवेदना और पीड़ा साफ झलक रही थी।

रेणु के लिए यह कहानी केवल एक साहित्यिक रचना नहीं थी, बल्कि उनके जीवन के अनुभवों और भावनाओं का सजीव चित्रण थी। उस कहानी का अंत उसके पूरे भाव को परिभाषित करता था। यदि उसे बदल दिया जाता, तो पूरी कहानी का अर्थ ही बदल जाता। शैलेंद्र ने इस गहराई को समझा और बिना किसी हिचकिचाहट के यह निर्णय लिया कि फिल्म के अंत में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कुछ बातें लाभ-हानि के दायरे से परे होती हैं और कला उन्हीं में से एक है। उनका यह निर्णय केवल एक फिल्म के संदर्भ में नहीं था, बल्कि यह उस विचारधारा के खिलाफ एक साहसिक कदम था, जो हर चीज को बाजार के हिसाब से ढालने की कोशिश करती है। उन्होंने यह दिखाया कि सच्चा कलाकार वही होता है, जो अपनी रचना के प्रति पूरी ईमानदारी और निष्ठा रखता है, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। यह एक ऐसा साहस था, जो हर किसी में नहीं होता।

समय के साथ यह सिद्ध हो गया कि शैलेंद्र का निर्णय सही था। भले ही शुरुआत में फिल्म को वह व्यावसायिक सफलता नहीं मिली, जिसकी उम्मीद की जाती है, लेकिन उसकी गुणवत्ता और गहराई को धीरे-धीरे लोगों ने समझा। फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और आज यह भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है। यह केवल एक फिल्म की सफलता नहीं, बल्कि उस सोच की जीत थी, जो कला को उसके मूल रूप में स्वीकार करने की बात करती है।

यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल तात्कालिक लाभ में नहीं होती, बल्कि वह उस स्थायित्व में होती है, जो समय के साथ और मजबूत होता जाता है। आज जब हम 'तीसरी कसम' को देखते हैं, तो हमें उसमें केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक युग की संवेदनाएं, संघर्ष और सादगी दिखाई देती है। यही वह विशेषता है, जो किसी भी कृति को कालजयी बनाती है।

आज के समय में, जब हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और सफलता को केवल आंकड़ों में मापा जाता है, तब यह कहानी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि अगर हम अपने कार्य के प्रति सच्चे हैं और उसमें अपनी आत्मा को झोंक देते हैं, तो सफलता देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलती है। और वह सफलता केवल व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि वह समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बनती है।

शैलेंद्र और रेणु की यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि सृजन केवल एक व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह संवेदनाओं और विचारों का साझा अनुभव है। जब दो सृजनशील व्यक्तित्व एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं और एक-दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तब उनकी कृति में एक अद्भुत गहराई और सच्चाई आ जाती है। यही कारण है कि 'तीसरी कसम' आज भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रभावशाली है, जितनी वह अपने समय में थी। अंततः, यह कहा जा सकता है कि कला का असली धर्म उसकी सच्चाई में है। जब कोई कलाकार अपने सृजन के प्रति ईमानदार रहता है, तो उसकी कृति अपने आप में एक संदेश बन जाती है। शैलेंद्र ने अपने निर्णय से यह साबित कर दिया कि कला को कभी भी समझौते का विषय नहीं बनाया जा सकता। उनका यह साहस और प्रतिबद्धता आज भी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है, जो अपने कार्य में उत्कृष्टता और सच्चाई की तलाश करता है। यही वह मूल्य हैं, जो किसी भी समाज को समृद्ध और संवेदनशील बनाते हैं, और यही वह आधार हैं, जिन पर सच्ची कला का निर्माण होता है।

विकास में भेदभाव का शिकार हो रहे हैं प्रमुख तीर्थस्थल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ससंदीय क्षेत्र होने के कारण काशी में जहां तरक्की और घोषणाओं की बरसात हो रही है, वहीं देश के दूसरे प्रमुख हिन्दू तीर्थ स्थल विकास की बाट जोह रहे रहे हैं। मोदी का निर्वाचन क्षेत्र होने के कारण केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पूरा जोर काशी तक सीमिट कर रहा गया है। यदि यह मान भी लिया जाए कि काशी हिन्दुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है, इसलिए इसके विकास की दरकार है, तो ऐसे में देश के प्रमुख राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अन्य तीर्थ स्थल विकास की दौड़ में काशी से काफी पीछे क्यों हैं। कारण साफ नजर आता है कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र होने के कारण काशी में विकास की गंगा बह रही, वहीं अन्य प्रमुख धार्मिक स्थल वाले जिले बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में विकास के तहत कुल 48,459 करोड़ रुपय की लागत से 580 परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया है। काशी के विकास की घोषणाओं की शुरुआत मोदी के पहली बार सांसद बनने के साथ ही शुरु हो गई थी। यह सिलसिला लगातार जारी है। हाल ही में पीएम मोदी ने अपने दो दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान 6332 करोड़ रुपये की कुल 163 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें गंगा पर सिग्नेचर ब्रिज सबसे बड़ी परियोजना है। जिसकी लागत करीब 2464.46 करोड़ है। यह ब्रिज काशी की कनेक्टिविटी और ट्रैफिक व्यवस्था को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री के हाथों 1054.69 करोड़ की 50 परियोजनाओं का लोकार्पण और 5277.39 करोड़ की 113 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया।

काशी के अलावा देश के अन्य प्रमुख तीर्थ स्थल वाले जिलों में विकास चींटी की रफ्तार से रेंग रहा है या फिर उसकी सुध नहीं ली जा रही है। काशाी के अलावा देश के प्रमुख हिन्दू तीर्थ स्थलों में आधारभूत सुविधाओं की बेहद कमी है। वैष्णों देवी के लिए प्रसिद्ध कटरा जिले में मूसलाधार बारिश के दौरान भूस्खलन की गंभीर समस्या है। जम्मू और कटरा के बीच सड़क और रेल संपर्क अक्सर टूट जाता है। विशेष रूप से, 2025 की बाढ़ के बाद से ट्रेनों का रद्दीकरण और पुलों (जैसे कठुआ, उधमपुर के पास) को नुकसान ने यात्रा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका दिया है। कटरा में स्मार्ट सड़कों, सुव्यवस्थित पार्किंग, और आधुनिक बुनियादी ढांचे की कमी है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को संभालने के लिए मौजूदा सुविधाएं नाकाफी हैं। बढ़ती भीड़ के कारण गर्मियों में पेयजल और निरंतर बिजली आपूर्ति की समस्या बनी रहती है। लगातार निर्माण, वनों की कटाई और भीड़भाड़ के कारण पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

राम मंदिर के विख्यात अयोध्या में बाल विकास विभाग की एक रिपोर्ट ने जिले में कुपोषण की चिंताजनक स्थिति को उजागर की है। जिले के 2,381 आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 2,28,018 बच्चों की जांच में 7,520 बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। इनमें 1,199 बच्चे अति कुपोषित (सैम) और 6,321 बच्चे मध्यम गंभीर कुपोषित (मैम) श्रेणी में हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 264 और 2024-25 में 286 अति कुपोषित बच्चों को पुनर्वास केंद्र भेजा गया। विकास परियोजनाओं के कारण हजारों लोग, विशेषकर छोटे व्यापारी और गरीब, अपने पुश्तैनी आवासों और व्यवसायों से विस्थापित हो गए हैं। परियोजनाओं के कारण उड़ने वाली धूल और निर्माण सामग्री से स्थानीय लोगों को सांस संबंधी बीमारियां हो रही हैं। जल भराव और सीवर के गंदे पानी के घरों में घुसने की समस्या से लोग लंबे समय से परेशान हैं। पुरानी अयोध्या (फैजाबाद) और अयोध्या धाम के बीच आवागमन में मुश्किल हो रही है।

देश के 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल केदारनाथ के रुद्रप्रयाग जिले के कई सुदूरवर्ती गांव अभी भी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव से जूझ रहे हैं, जहाँ आपदा प्रभावित क्षेत्रों में संपर्क मार्ग बाधित होने और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण लोगों को स्वास्थ्य उपचार के लिए भटकना पड़ता है। भारी बारिश के कारण संपर्क मार्ग बाधित होना भी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच में एक बड़ी बाधा है। जिले भर में लगभग 25 जल स्रोत सूख चुके हैं, जिससे पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। पानी की कमी से नाराज लोग जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। इसी तरह उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में तेजी से बढ़ते शहरीकरण, धार्मिक पर्यटन के दबाव और प्रशासनिक चुनौतियां मौजूद हैं। नालों और सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण के कारण जल निकासी बाधित हो रही है। मानसून से पहले नालों पर अतिक्रमण के कारण जलभराव का खतरा बना रहता है। हरकी पैड़ी और आसपास के क्षेत्रों में भिक्षावृत्ति एक बड़ी समस्या है। चारधाम यात्रा के सुचारू न रहने या व्यवस्थाओं के कारण स्थानीय होटलों और पर्यटन व्यवसाय पर भी असर पड़ रहा है।

कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में 30,000 करोड़ से अधिक की ब्रज मास्टर प्लान परियोजनाओं और नई आवासीय योजनाओं के लिए 850 करोड़ के बावजूद, कई विकास कार्य फाइलों में अटके हैं। वर्ष 2026-2030 के मास्टर प्लान के अंतर्गत शहर को हाई-स्पीड कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने का विज़न है, लेकिन प्रशासनिक प्रक्रियाओं के चलते जमीनी स्तर पर गति धीमी है। मथुरा-वृंदावन में वर्षभर धार्मिक आयोजनों की लंबी श्रृंखला चलती रहती है। प्रमुख आयोजनों में होलिकोत्सव, मुड़िया मेला, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, झूलन उत्सव, कार्तिक मास, गोवर्धन पूजा और ब्रज की विभिन्न परिक्रमाएं शामिल हैं। आयोजनों के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या 8 से 10 लाख तक पहुंच जाती है।

अभियान

मंत्र शक्ति और लक्ष्मी कृपा का आध्यात्मिक विज्ञान

भारतीय सनातन परंपरा में ध्वनि को सृष्टि का मूल आधार माना गया है। वेदों में वर्णित "नाद ब्रह्म" की अवधारणा यह स्पष्ट करती है कि सम्पूर्ण ब्रह्मांड एक सूक्ष्म स्पंदन पर आधारित है। यही स्पंदन जब मंत्र के रूप में व्यवस्थित होता है, तो वह साधक के जीवन में गहरे परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। विशेष रूप से धन, समृद्धि और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी मां लक्ष्मी की आराधना में मंत्रों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। शुक्रवार का दिन उनकी उपासना के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन की ऊर्जा स्वयं समृद्धि और सौंदर्य के तत्वों से जुड़ी होती है। जब कोई साधक श्रद्धा और एकाग्रता के साथ लक्ष्मी मंत्रों का जाप करता है, तो वह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं करता, बल्कि वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ स्वयं को जोड़ता है। यह जुड़ाव धीरे-धीरे उसकी मानसिक, भावनात्मक और भौतिक स्थिति को परिवर्तित करने लगता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने बीज मंत्रों को अत्यंत शक्तिशाली माना है। बीज मंत्र वास्तव में ऊर्जा के संक्षिप्त सूत्र होते हैं, जिनमें एक विशेष कंपन छिपा होता है।

"ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं" यह बीज मंत्र छोटा अवश्य है, लेकिन इसकी शक्ति अत्यंत गूढ़ और प्रभावशाली है। "श्रीं" को लक्ष्मी का मूल बीज माना जाता है, जो धन और समृद्धि का प्रतीक है। "ह्रीं" आंतरिक शुद्धता और आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेत देता है, जबकि "क्लीं" आकर्षण और सकारात्मक ऊर्जा को खींचने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। जब इन तीनों का संयुक्त जाप किया जाता है, तो यह साधक के जीवन में न केवल आर्थिक उन्नति लाता है, बल्कि मानसिक संतुलन और आत्मिक शांति भी प्रदान करता है।

मंत्र जाप का वास्तविक प्रभाव तब प्रकट होता है, जब उसे नियमितता और विश्वास के साथ किया जाए। आज के आधुनिक युग में, जहां लोग त्वरित परिणामों की अपेक्षा करते हैं, वहां यह समझना आवश्यक है कि मंत्र साधना एक प्रक्रिया है, जो धीरे-धीरे फल देती है। यह ठीक उसी प्रकार है, जैसे कोई बीज बोने के बाद उसे समय, जल और पोषण की आवश्यकता होती है। यदि साधक धैर्य बनाए रखता है, तो निश्चित ही उसे उसके प्रयासों का फल प्राप्त होता है।

महालक्ष्मी मंत्र "ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः" अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। इस मंत्र में देवी के सौम्य और कृपालु स्वरूप का आह्वान किया जाता है। "कमले कमलालये" शब्द यह दर्शाते हैं कि देवी कमल में निवास करती हैं, जो पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक है। इस मंत्र का जाप साधक के जीवन में सौभाग्य, ऐश्वर्य और संतुलन लाने में सहायक होता है। विशेष रूप से यदि इसे शुक्रवार के दिन दीपक जलाकर और स्वच्छ मन से जपा जाए, तो इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है।

मंत्रों का प्रभाव केवल बाहरी परिस्थितियों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह साधक के भीतर भी परिवर्तन लाता है। जब व्यक्ति नियमित रूप से मंत्र जाप करता है, तो उसका मन स्थिर होता है, विचार सकारात्मक होते हैं और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यही आंतरिक परिवर्तन बाहरी सफलता का कारण बनता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए, तो लक्ष्मी कृपा केवल धन प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और संतुष्टि प्रदान करती है।

"या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता" यह श्लोक देवी की सर्वव्यापकता को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि देवी लक्ष्मी हर जीव में किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं। जब साधक इस मंत्र का जाप करता है, तो वह यह स्वीकार करता है कि समृद्धि केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हर छोटे-बड़े अनुभव में भी मौजूद है। यह भावना व्यक्ति को कृतज्ञता सिखाती है, जो वास्तविक समृद्धि का आधार है।

जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए "ॐ ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः" मंत्र का विशेष महत्व है। यह मंत्र साधक के मार्ग में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और कार्यों में सहजता लाता है। जब कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण कार्य से पहले इस मंत्र का जाप करता है, तो उसका मन शांत और केंद्रित हो जाता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है।

आर्थिक तंगी दूर करने के लिए "ॐ ह्रीं श्री क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरये" मंत्र का जाप अत्यंत लाभकारी माना गया है। यह मंत्र न केवल धन की प्राप्ति के लिए, बल्कि आर्थिक स्थिरता और कर्ज से मुक्ति के लिए भी प्रभावी है। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि मंत्र केवल एक साधन है, इसके साथ कर्म और प्रयास भी उतने ही आवश्यक हैं। यदि व्यक्ति केवल मंत्र जाप करे, लेकिन अपने कार्यों में ईमानदारी और परिश्रम न रखे, तो उसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। वास्तव में, लक्ष्मी कृपा का अर्थ केवल धन प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह एक संतुलित और समृद्ध जीवन जीने की कला है। जब व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन, कृतज्ञता और सकारात्मकता को अपनाता है, तभी वह वास्तविक समृद्धि का अनुभव कर पाता है। मंत्र साधना इस प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाती है, क्योंकि यह साधक को भीतर से मजबूत बनाती है।

आज के समय में, जब आर्थिक प्रतिस्पर्धा और मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है, तब लक्ष्मी मंत्रों की साधना एक संतुलन प्रदान करती है। यह व्यक्ति को यह सिखाती है कि समृद्धि केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष से भी आती है। जब दोनों का संतुलन बनता है, तभी जीवन वास्तव में सफल और पूर्ण बनता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि मंत्र शक्ति एक गूढ़ विज्ञान है, जो सही तरीके से अपनाने पर जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल मंत्र जाप ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके साथ श्रद्धा, धैर्य और सत्कर्म भी आवश्यक हैं। जब ये सभी तत्व एक साथ मिलते हैं, तब व्यक्ति के जीवन में न केवल आर्थिक उन्नति होती है, बल्कि वह एक संतुलित, सुखी और संतुष्ट जीवन भी जी पाता है। यही लक्ष्मी साधना का वास्तविक उद्देश्य है और यही उसका सबसे बड़ा लाभ भी।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

गुजरात सरकार की i-Hub पहल का कमाल : उद्यमी बन रहे हैं समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम

▶▶ आग बुझाने के इकोफ्रेंड्ली सॉल्यूशन ‘अचूक’ को मिला गुजरात सरकार का सहयोग

▶▶ आई-हब की सहायता से अहमदाबाद की महिला उद्यमी ने बच्चों को फास्टफूड से सुपरफूड की ओर मोड़ा

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई दिशा दी है। उनके विजन का अनुकरण करके गुजरात आज उद्यमिता के सुदृढ़ केन्द्र के रूप में उभर कर आया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात आज पाँचवीं बार स्टार्टअप रैंकिंग में अग्रसर बना है, जो इस क्षेत्र में हुए सुव्यवस्थित प्रयासों को दर्शाता है। राज्य में गुजरात स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन हब (i-Hub) द्वारा इनोवेशन को निरंतर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। स्टार्टअप्स को वित्तीय, ढाँचा, टेक्निकल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तथा नियमनकारी सहायता प्रदान किए जाते हैं; जिसके परिणामस्वरूप ये स्टार्टअप्स आज समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम बन रहे हैं।

आग बुझाने के इकोफ्रेंड्ली सॉल्यूशन ‘अचूक’ को मिला आई-हब का सहयोग

आग लगने की बढ़ती घटनाओं के बीच जान-माल के साथ पर्यावरण की रक्षा करना एक बड़ी चुनौती बन रहा है। अहमदाबाद स्थित राहुल शाह तथा उनकी टीम ने इस चुनौती को ध्यान में रखकर आग बुझाने के इकोफ्रेंड्ली सॉल्यूशन ‘Achuk एन्वायर्नमेंटल सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड’ विकसित किया है। आधुनिक समय में नायलॉन तथा पीवीसी जैसे सिंथेटिक मटेरियल के बढ़ते उपयोग के कारण आग अधिक तेजी से फैलती है और बचाव के लिए बहुत कम समय रहता है। ऐसी स्थिति में ‘अचूक’ का सॉल्यूशन परंपरागत अग्निशामक साधनों (उपकरणों) की तुलना में अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। पानी के साथ मिश्रित होने में सक्षम यह टेक्नोलॉजी कार्बन उत्सर्जन घटाती है, पानी का बचाव करती है और पर्यावरण प्रदूषण कम करती है।

‘अचूक’ के संस्थापक श्री राहुल शाह ने कहा, “गुजरात सरकार के सहयोग से हमारे स्टार्टअप को प्रारंभिक चरण से ही सुदृढ़ सपोर्ट मिला है। सीड स्टार्टअप फंड अंतर्गत प्राप्त सहायता से प्रोडक्ट के अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन मिला है तथा इनक्यूबेशन सपोर्ट द्वारा मार्गदर्शन, पेटेंट, पंजीकरण प्रक्रिया और एग्जीबिशन में भाग लेने के अवसर प्राप्त हुए। आई-हब अंतर्गत प्राप्त हुए सहयोग के कारण आज हमारा स्टार्टअप सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है।”

आई-हब की सहायता से अहमदाबाद की महिला उद्यमी ने बच्चों को फास्टफूड से सुपरफूड की ओर मोड़ा

आज की फास्ट लाइफ में जब फास्टफूड का प्रभाव बढ़ रहा है, तब उसके समक्ष कोई स्वास्थ्यप्रद विकल्प मिले, तो ? अहमदाबाद की डॉ. डिंपल गणात्रा का यह विचार आज आई-हब के सपोर्ट से एक फुल फ्लेज्ड स्टार्टअप में परिवर्तित हुआ है। दो दशक से भी अधिक समय तक सर्जन के रूप में सेवा देने वालीं डॉ. डिंपल गणात्रा ने अनुचित जीवनशैली तथा फास्टफूड के कारण होने वाले रोगों एवं बच्चों में पोषण के अभाव को ध्यान में रखकर वर्ष 2022 में ‘HealthyGrabz’ की शुरुआत की थी। हेल्दीग्रैब्ज की विशेषता यह है कि वह भिन्न-भिन्न सब्जियों के मूल पोषण मूल्यों को बनाए रखते हुए उनसे चिप्स बनाता है।

गुजरात सरकार का आभार व्यक्त करते हुए डॉ. डिंपलबेन ने कहा, “आई-हब जैसा इनक्यूबेशन सपोर्ट सिस्टम केवल मार्गदर्शन ही नहीं; बल्कि स्टार्टअप को नेटवर्किंग, डीलर के साथ कनेक्टिविटी एवं व्यावसायिक चुनौतियों के निवारण के लिए एक सुदृढ़ प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है। किसी भी समस्या या दिक्कत के समय उचित मार्गदर्शन आसानी से मिलता है, जो उद्यमियों को आत्मविश्वास प्रदान करता है। विशेषकर महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने में राज्य सरकार का सकारात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट दिखाई देता है।”

गुजरात सरकार के समर्थन से सर्बोटेक एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड को मिली नई दिशा

आणंद स्थित सर्बोटेक एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा स्टार्टअप है, जिसने परंपरागत ब्रेन डेवलपमेंट पद्धतियों को आधुनिक न्यूरोकॉग्निटिव टेक्नोलॉजी के साथ एकीकृत कर अनूठा उत्पाद विकसित किया है। यह उत्पाद विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन कर उनकी ब्रेन ट्रेनिंग को अधिक प्रभावशाली बनाता है।

श्वेता प्रजापति ने अपने स्टार्टअप की सफलता का श्रेय गुजरात सरकार को देते हुए कहा, “हाल में हमारा स्टार्टअप लगभग 500 विद्यार्थियों पर अनुसंधान कर रहा है। सर्बोटेक के उपकरणों से विद्यार्थियों की मनोस्थिति का विश्लेषण हो सकता है, जिससे उनके स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। मैंने कई स्टार्टअप्स को फंडिंग तथा सपोर्ट के अभाव में विफल होते देखा है, परंतु आई-हब जैसे प्लेटफॉर्म के सहयोग से हमारा स्टार्टअप आज समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बन रहा है।”

आई-हब द्वारा लगभग 720 स्टार्टअप्स को सीधी सहायता मिली, 4000 कुशल रोजगार का सृजन हुआ

गुजरात में स्टार्टअप तथा नवाचार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अहमदाबाद में गुजरात स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन हब (आई-हब) की स्थापन की गई थी। आज यह पहल राज्य में नवाचार, रोजगार एवं उद्यमिता को वेग देने वाला सशक्त प्लेटफॉर्म बन गई है। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में स्थापित इस अत्याधुनिक परिसर में लगभग 500 स्टार्टअप्स के एक साथ काम कर सकने की व्यवस्था है।

उल्लेखनीय है कि आई-हब द्वारा अब तक लगभग 720 स्टार्टअप्स को सीधी सहायता दी गई है और स्टार्टअप सृजन सीड सपोर्ट योजनांतर्गत 466 स्टार्टअप्स को 28 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मंजूर की गई है। आई-हब के इनक्यूबेटेड स्टार्टअप्स द्वारा राज्य में लगभग 4000 कुशल रोजगार का सृजन हुआ है और इन स्टार्टअप्स की कुल मार्केट वैल्यू लगभग 3569 करोड़ रुपए तक पहुँची है, जो राज्य के सशक्त स्टार्टअप इकोसिस्टम को दर्शाती है।

धूप से पैरों पर आ गए चप्पल के निशान तो घरेलू उपाय कारगर होंगे-शहनाज़ हुसैन

गर्मियों का मौसम अपने साथ जहां धूप, तपिश और उमस लेकर आता है, वहीं यह हमारी त्वचा के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन जाता है। खासतौर पर पैरों की त्वचा, जो अक्सर सैंडल या चप्पल पहनने की वजह से खुली रहती है, इस मौसम में सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। तेज धूप के सीधे संपर्क में आने से त्वचा का रंग झुलसने लगता है और पैरों पर चप्पल के डिजाइन जैसे निशान उभर आते हैं। यह स्थिति देखने में न केवल असमान लगती है, बल्कि कई बार आत्मविश्वास को भी प्रभावित करती है।

प्रख्यात सौंदर्य विशेषज्ञ शहनाज़ हुसैन के अनुसार, इस समस्या से निपटने के लिए महंगे सैलून ट्रीटमेंट ही एकमात्र विकल्प नहीं हैं। घर में मौजूद साधारण सामग्री से भी आप अपने पैरों की खोई हुई चमक और कोमलता वापस पा सकते हैं। जरूरी है तो बस थोड़ी नियमितता और सही देखभाल की समझ।

गर्मी के दिनों में धूल, मिट्टी और पसीने का असर पैरों पर जल्दी दिखने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कई दिनों से पैरों की सफाई नहीं की गई हो और उन पर मैल जम गई हो। ऐसे में सबसे पहला और जरूरी कदम है—सही तरीके से सफाई। स्क्रबिंग इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा है, जो त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाकर नई त्वचा को उभरने का मौका देता है।

घरेलू स्क्रब के रूप में टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा और नींबू का मिश्रण काफी प्रभावी माना जाता है। बेकिंग सोडा त्वचा को एक्सफोलिएट करता है, जबकि नींबू में मौजूद विटामिन C त्वचा की रंगत को निखारने में मदद करता है। इस मिश्रण को पैरों पर लगाकर हल्के हाथों से स्क्रब करने से टैनिंग धीरे-धीरे कम होने लगती है। नींबू के छिलके से स्क्रब करना भी एक अच्छा उपाय है, क्योंकि इससे त्वचा की गहराई से सफाई होती है।

इसी तरह, कॉफी और शहद का मिश्रण भी एक बेहतरीन प्राकृतिक स्क्रब के रूप में काम करता है। कॉफी के कण त्वचा की सफाई करते हैं और शहद उसे नमी प्रदान करता है। यह संयोजन पैरों को न केवल साफ करता है, बल्कि उन्हें मुलायम और चमकदार भी बनाता है।

नींबू और खीरे का मिश्रण त्वचा को ठंडक और ताजगी देने के लिए जाना जाता है। खीरे का रस त्वचा को सुकून देता है, जबकि नींबू टैनिंग को हल्का करने में मदद करता है। इस मिश्रण को कॉटन से पैरों पर लगाकर कुछ समय बाद धो लेने से त्वचा में धीरे-धीरे सुधार दिखाई देने लगता है।

घरेलू मास्क भी इस समस्या का प्रभावी समाधान हैं। आलू का रस, दही, बेसन, नींबू और शहद मिलाकर बनाया गया पेस्ट एक संपूर्ण स्किन ट्रीटमेंट का काम करता है। आलू त्वचा को हल्का करता है, दही में मौजूद लैक्टिक एसिड मृत त्वचा को हटाता है, और शहद त्वचा को हाइड्रेट करता है। इस मास्क को पैरों पर लगाकर हल्के-हल्के रगड़ते हुए हटाने से त्वचा साफ और कोमल बनती है।

बेसन और दही का उपयोग भारतीय घरों में लंबे समय से सौंदर्य के लिए किया जाता रहा है। यह मिश्रण त्वचा को साफ करने और टैनिंग हटाने में बेहद असरदार है। इसमें नींबू का रस मिलाने से इसका प्रभाव और बढ़ जाता है।

एक और खास घरेलू उपाय है टैन रिमूविंग पेस्ट, जिसमें इनो, नींबू का रस, नारियल तेल, शैंपू, कॉफी और आटा मिलाया जाता है। यह मिश्रण त्वचा की गहराई से सफाई करता है और टैनिंग को कम करने में मदद करता है। इसे हल्के हाथों से रगड़ने पर अच्छे परिणाम मिलते हैं।

लेकिन इन सभी उपायों के साथ सबसे जरूरी है—मॉइस्चराइजेशन। दिनभर धूप और धूल में रहने के बाद पैरों को गुनगुने पानी से धोना और फिर उन्हें अच्छी तरह सुखाकर मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है। रात को सोने से पहले पैरों को मॉइस्चराइज करने से त्वचा नरम और स्वस्थ बनी रहती है।

संतरे के छिलके का पाउडर और कच्चा दूध भी टैनिंग हटाने में मददगार होते हैं। संतरे में मौजूद विटामिन C त्वचा को निखारता है और इसके छिलके के कण त्वचा की सफाई करते हैं। चावल का आटा मिलाने से यह मिश्रण और प्रभावी हो जाता है।

यह सभी उपाय हमें यह सिखाते हैं कि सुंदरता के लिए महंगे उत्पादों की जरूरत नहीं होती। हमारी रसोई में ही ऐसे कई तत्व मौजूद हैं, जो हमारी त्वचा को

देश की स्थिति, प्रदूषण, बेरोजगारी और गांवों की उपेक्षा: विकास के दुष्प्रभावों पर एक चिंताजनक नजर

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। आज देश की हालत ऐसी है कि “दुल्हा-दुल्हन की मृत्यु हो जाए तो भी देश कचरे के ढेर में बदल जाएगा”, “देश गड्ढे में गिरता जा रहा है, नीतियां वही रहेंगी”, “अपना काम खत्म होने पर जनता किराए का बोझ उठाएगी”, “नेता धन और पद के पीछे पागल हैं?” ऐसा देश पहले कभी नहीं देखा गया। ये सब पतन के लक्षण हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, देश एक भयानक संकट में है। देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, लाखों लोगों को दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है।

गांवों में समान शिक्षा नहीं है, न ही चिकित्सा सुविधाएं हैं, न ही परिवहन सुविधाएं हैं, सब कुछ शहरों में उपलब्ध है। शासक शहरों के प्रति पक्षपाती हैं। गांवों के शासकों को कोई परवाह नहीं है। शहरों में छोटे-बड़े उद्योग फल-फूल रहे हैं, वे बहुत अधिक पानी का उपयोग करते हैं और लोग पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। साथ ही, उद्योगों का अपशिष्ट जल नदियों और झीलों में बहाया जाता है। यही कारण है कि उनका पानी पीने योग्य नहीं रह गया है। वाहनों और उद्योगों के धुएं के कारण स्वच्छ हवा दुर्लभ हो गई है। क्या शहरों में प्रदूषण बढ़ गया है? और इन सबका असर वातावरण पर पड़ रहा है। यानी, अत्यधिक गर्मी, सर्दी, बारिश या तूफान की मात्रा बढ़ गई है। जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र और कृषि के लिए भी हानिकारक है।

रासायनिक उर्वरकों और दवाओं ने गाँव की ज़मीन को बर्बाद कर दिया है। मिट्टी के पोषक तत्व सोख लिए गए हैं। उर्वरकों की खपत बढ़ गई है। उर्वरक और दवाएँ महँगी हो गई हैं। फसलों में कीटों को नियंत्रित करने के लिए अधिक दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है। क्या जहरीली दवाएँ हवा को प्रदूषित करती हैं, मिट्टी को खराब करती हैं और लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुँचाती हैं? क्या यह जहर बारिश के पानी के साथ बहकर नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है और समुद्र में मछलियाँ आदि नष्ट हो जाती हैं? अन्य जानवर और पक्षी भी मर रहे हैं। क्या जहर हर जगह फैल रहा है? क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले घोंघे और इल्लियाँ गायब होने लगे हैं?

प्रकृति का चक्र टूट रहा है। कृषि में ट्रैक्टरों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए बैलों की संख्या कम होती जा रही है। देश सुधार के पथ पर चलकर विनाश की ओर बढ़ रहा है। और विकास के नाम पर विदेशी कर्ज के पहाड़ कम होते जा रहे हैं। कहते हैं, मेरा भारत महान है।

वैश्विक तूफानों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था बनी मजबूती की मिसाल

नई दिल्ली। दुनिया जब एक के बाद एक आर्थिक और भू-राजनीतिक संकटों से जूझ रही है, तब भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस संतुलन, धैर्य और मजबूती का परिचय दिया है, उसने वैश्विक मंच पर एक नई पहचान बनाई है। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी Moody’s Ratings की ताजा रिपोर्ट इसी सच्चाई को रेखांकित करती है, जिसमें भारत को उभरते बाजारों में सबसे लचीली और मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी बताया गया है। यह उपलब्धि किसी एक नीति या फैसले का परिणाम नहीं, बल्कि वर्षों से बनाए गए आर्थिक ढांचे, दूरदर्शी नीतियों और संतुलित वित्तीय प्रबंधन का नतीजा है। साल 2020 के बाद से वैश्विक अर्थव्यवस्था ने जिन कठिन दौरों का सामना किया है, वह अभूतपूर्व रहा है। कोविड-19 महामारी ने जहां पूरी दुनिया की आर्थिक गतिविधियों को ठप कर दिया, वहीं उसके बाद आई वैश्विक महंगाई, अमेरिका की सख्त मौद्रिक नीति, 2023 का बैंकिंग संकट और हाल के वर्षों में बढ़ते व्यापारिक तनावों ने आर्थिक अनिश्चितता को और गहरा किया। इन सबके बीच कई उभरती अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा गईं, लेकिन भारत ने न केवल खुद को संभाले रखा, बल्कि मजबूती के साथ आगे भी बढ़ता रहा।

इस मजबूती के पीछे सबसे बड़ा आधार बना देश का विशाल विदेशी मुद्रा भंडार। इस भंडार ने वैश्विक झटकों के दौरान रुपये की अस्थिरता को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब दुनिया के कई देशों की मुद्राएं तेजी से गिरावट का सामना कर रही थीं, तब भारत ने अपने भंडार के बल पर विनिमय दर में संतुलन बनाए रखा। इससे न केवल बाजार में स्थिरता बनी रही, बल्कि विदेशी निवेशकों का भरोसा भी कायम रहा। निवेशकों के लिए यह विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होती है, और भारत ने इसे बनाए रखने में सफलता हासिल की। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भारत का मौद्रिक नीति ढांचा उसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। Reserve Bank of India की नीतियों ने महंगाई को नियंत्रित रखने, ब्याज दरों को संतुलित करने और आर्थिक गतिविधियों को सुचारू बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। स्थिर मुद्रास्फीति अपेक्षाएं और आवश्यकता पड़ने पर विनिमय दर में लचीलापन, यह दर्शाता है कि भारत की आर्थिक नीति केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि दूरदर्शी भी है।

हालांकि, इस सकारात्मक तस्वीर के बीच कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। उच्च ऋण बोझ और राजकोषीय संतुलन की कमजोर स्थिति ऐसे कारक हैं, जो भविष्य में आर्थिक दबाव बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद, भारत ने जिस तरह से नीतिगत फैसलों के माध्यम से स्थिरता बनाए रखी है, वह उसकी आर्थिक क्षमता को दर्शाता है। सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच समन्वय ने इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मूडीज की इस रिपोर्ट में भारत के साथ-साथ इंडोनेशिया, मेक्सिको, मलेशिया, थाईलैंड, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, तुर्किये और अर्जेंटीना जैसे देशों का भी अध्ययन किया गया। इन सभी देशों ने वैश्विक दबावों का सामना अपने-अपने तरीके से किया, लेकिन भारत का प्रदर्शन इन सबके बीच अलग और अधिक संतुलित रहा। यह अंतर केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि आर्थिक प्रबंधन की गुणवत्ता में भी दिखाई देता है।

भारत की अर्थव्यवस्था की एक और खासियत उसकी घरेलू मांग है, जो उसे वैश्विक संकटों से काफी हद तक सुरक्षित रखती है। जब बाहरी बाजारों में अनिश्चितता बढ़ती है, तब घरेलू उपभोग और निवेश अर्थव्यवस्था को सहारा देते हैं। यही कारण है कि भारत की विकास दर अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक स्थिर बनी रही है।

भीषण गर्मी में यात्रियों को राहत: भावनगर मंडल के बोटाद स्टेशन पर निःशुल्क छाछ एवं शीतल पेयजल का वितरण

भीषण गर्मी एवं बढ़ते तापमान के मद्देनज़र यात्रियों को राहत प्रदान करने हेतु पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा जनहित में विशेष पहल की गई है। इस क्रम में दिनांक 05 मई, 2026 (मंगलवार) को बोटाद रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए निःशुल्क छाछ एवं शीतल पेयजल वितरण की व्यवस्था की गई।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि बोटाद रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म क्षेत्र में यात्रियों विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों,

महिलाओं एवं बच्चों को छाछ एवं ठंडा पेयजल उपलब्ध कराया गया, जिससे उन्हें भीषण गर्मी से काफी राहत मिली।

निःशुल्क छाछ वितरण सेवा में “माँ महावीर ग्रुप-बोटाद” का सराहनीय सहयोग प्राप्त हुआ। इसी प्रकार यात्रियों के लिए निःशुल्क शीतल पेयजल वितरण में “जायन्ट्स ग्रुप ओफ बोटाद” का सहयोग रहा। “माँ महावीर ग्रुप-बोटाद” ने यात्रियों के लिए निःशुल्क 100 लीटर छाछ की व्यवस्था की तथा “जायन्ट्स ग्रुप ओफ बोटाद” ने यात्रियों हेतु 400 लीटर ठंडा पानी की व्यवस्था की।

स्टेशन पर इन व्यवस्थाओं को सफलतापूर्वक संचालित करने में भावनगर मंडल के वाणिज्य विभाग के निरीक्षकों, टिकट चेकिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई तथा वितरण कार्य को सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न किया।

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक (DRM) श्री दिनेश वर्मा ने कहा, “भीषण गर्मी के दौरान यात्रियों को राहत प्रदान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भावनगर मंडल द्वारा विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से इस प्रकार की जनहितकारी गतिविधियाँ निरंतर आयोजित की जा रही हैं। यह पहल हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता एवं यात्री-हित के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है।”

भावनगर मंडल द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं मानवीय सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती रहें। भीषण गर्मी के दौरान इस प्रकार की राहत सेवाएँ आगे भी निरंतर जारी रहेंगी।

सवाई माधोपुर में चीते की दस्तक से दहशत, रणथंभौर के आसपास गांवों में बढ़ी चिंता

सवाई माधोपुर। राजस्थान के वन्यजीव समृद्ध क्षेत्र रणथंभौर टाइगर रिजर्व के आसपास इन दिनों स्थिति सामान्य नहीं है। जंगल और इंसानी बस्तियों के बीच की सीमाएं जैसे धुंधली पड़ गई हैं। वजह है एक चीता—KP-2, जो मध्यप्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान से भटककर यहां पहुंच गया है और पिछले करीब 20 दिनों से लगातार अलग-अलग वन क्षेत्रों और आबादी वाले इलाकों के आसपास देखा जा रहा है।

इस एक जानवर की मौजूदगी ने पूरे इलाके का माहौल बदल दिया है। जो गांव कभी सुबह खेतों की चहल-पहल और बच्चों की आवाज़ों से गूंजते थे, वहां अब सन्नाटा और डर का माहौल है। कैलाशपुरी, दुमोदा और मोजीपुरा जैसे गांवों में लोग अब अपने घरों से निकलने में हिचक रहे हैं। खेतों की ओर जाने वाले रास्ते सूने पड़े हैं और कई किसानों ने तो अपनी खेती-किसानी के जरूरी काम तक रोक दिए हैं। ग्रामीणों के अनुसार, चीता कई बार अमरूद के बागानों और खेतों के आसपास घूमता देखा गया है। उसकी मौजूदगी ने लोगों को इतना डरा दिया है कि अब दिन में भी खेतों में जाना जोखिम भरा माना जा रहा है। जहां पहले किसान अपनी फसलों की देखभाल नियमित रूप से करते थे, अब वही फसलें पानी और देखभाल के अभाव में सूखने लगी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह केवल आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि उनकी पूरी जीवनचर्या पर असर डालने वाली स्थिति बन चुकी है।

स्थिति तब और गंभीर हो गई जब यह सामने आया कि चीते ने कुछ पालतू पशुओं का शिकार भी किया है। इसके बाद गांवों में डर और गहरा गया है। लोग अब बच्चों को अकेले बाहर भेजने से बच रहे हैं। जिन रास्तों से रोजाना बच्चे स्कूल जाते थे, उन रास्तों पर अब परिवार खुद बच्चों को रोक रहे हैं। कई परिवारों ने तो बच्चों को अस्थायी रूप से घर में ही रखने का निर्णय लिया है।

वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, KP-2 चीते का यह व्यवहार असामान्य नहीं है, क्योंकि जब बड़े शिकारी अपने मूल क्षेत्र से भटक जाते हैं तो वे भोजन और सुरक्षित इलाके की तलाश में मानव बस्तियों की ओर भी आ सकते हैं। लेकिन रणथंभौर जैसे संवेदनशील और घनी आबादी वाले वन क्षेत्र में यह स्थिति चिंता का विषय बन जाती है।

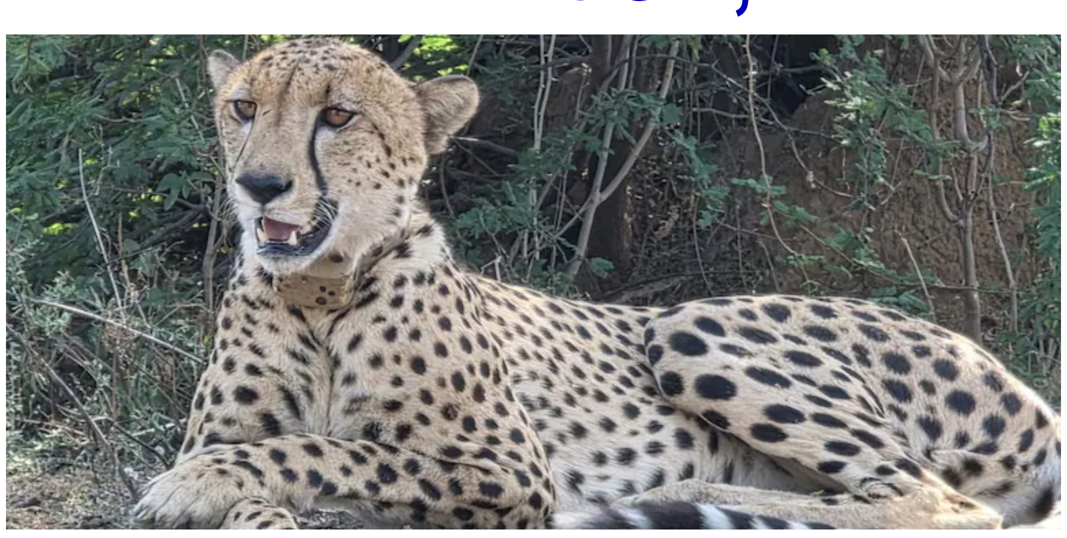

वन विभाग की टीमें लगातार इस चीते की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। कैमरा ट्रैप, ड्रोन और फील्ड स्टाफ की मदद से उसके मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि चीता किसी भी इंसानी जीवन को नुकसान न पहुंचाए और उसे सुरक्षित तरीके से नियंत्रित किया जाए।

हालांकि ग्रामीणों का गुस्सा और डर लगातार बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि सिर्फ निगरानी पर्याप्त नहीं है। उनका मानना है कि जब तक चीते को सुरक्षित रूप से पकड़कर किसी संरक्षित वन क्षेत्र में वापस नहीं ले जाया जाता, तब तक खतरा बना रहेगा। गांवों में यह मांग तेज हो रही है कि प्रशासन तुरंत कोई ठोस कदम उठाए।

इस बीच इलाके में रात के समय स्थिति और भी संवेदनशील हो जाती है। कई गांवों में लोग शाम होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहले जहां रातें सामान्य होती थीं, अब हर हल्की आवाज भी डर पैदा कर देती है। जंगल और गांव के बीच की दूरी जैसे खत्म हो गई हो।

वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने और अकेले खेतों या जंगल के किनारे न जाने की सलाह दी है। साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दी जाए। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सतर्कता जरूरी है क्योंकि वन्यजीव का व्यवहार कभी भी अप्रत्याशित हो सकता है।

यह घटना एक बार फिर इस सवाल को सामने लाती है कि जब जंगल सिकुड़ते हैं और इंसानी बस्तियां फैलती हैं, तो वन्यजीवों और मानव जीवन के बीच संघर्ष की स्थिति कैसे बनती है। रणथंभौर और कूनो जैसे क्षेत्रों के बीच वन्यजीवों की आवाजाही यह संकेत देती है कि प्रकृति और मानव समाज के बीच संतुलन बनाए रखना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।

फिलहाल पूरा क्षेत्र तनाव और सतर्कता के माहौल में है। गांवों की गलियों में सन्नाटा है और लोग सिर्फ एक ही उम्मीद कर रहे हैं कि यह दहशत जल्द खत्म हो और जीवन फिर से सामान्य हो सके।

पश्चिम रेल्वे

कैंटीन के काम के लिए मज़दूरों की भर्ती

मुख्य कार्यशाला प्रबंधक, EMU कार्यशाला, महालक्ष्मी, मुंबई - 400 013, ई-निविदा आमंत्रित करते हैं। सूचना संख्या: EL90/MX/2026-27/02 दिनांक 29.04.2026। कार्य का नाम: EMU कार्यशाला, महालक्ष्मी में कैंटीन के काम के लिए 900 कार्य दिवसों की अवधि हेतु श्रमिकों की नियुक्ति। कार्य की अनुमानित लागत: ₹ 1,96,54,392.44। EMD (बयाना राशि): ₹ 2,48,300/-। निविदा जमा करने और खोलने की तिथि और समय: निविदा दि.01.06.2026 को 12:00 बजे तक (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) जमा की जा सकती है। विवरण के लिए कृपया www.ireps.gov.in पर जाएं। 0066

हमें लाईक करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे-रतलाम मंडल

ई-निविदा सूचना

मंडल रेलप्रबंधक (बिजली/पॉवर शाखा) पश्चिम रेलवे रतलाम भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए "खुली निविदा" ई-निविदा के माध्यम से वेब साईट www.ireps.gov.in पर आमंत्रित करते है। विवरण इस प्रकार है। **क्र. सं. 1) ई टेंडरिंग संख्या: EL-2026-27-03. कार्य का नाम:** Ratlam Division - Improvement in various electrical items & cables arrangements at 16 stations under ABSS Balance work. **अनुमानित लागत:** ₹ 26082737.26 **बयाना राशी:** ₹ 521700.00 **कार्य की समापन अवधि:** 12 Months. **वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि:** 29/04/2026. **निविदा खुलने की तिथि:** 26/05/2026. **क्र. सं. 2) ई टेंडरिंग संख्या: EL-2026-27-04. कार्य का नाम:** Ratlam Division-Replacement & Repairing work of Pantry equipment's in LHB AC Pantry Car at IND and DADN based primary rakes for a period of two years. **अनुमानित लागत:** ₹ 9879257.26 **बयाना राशी:** ₹ 197600.00 **कार्य की समापन अवधि:** 24 Months. **वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि:** 29/04/2026. **निविदा खुलने की तिथि:** 02/06/2026. विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य शर्तें वेब साईट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है।

CRY/IND/35

हमें लाइक करें : facebook.com/WesternRly

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अडालज स्थित त्रिमंदिर परिसर में राजस्व विभाग के तीन दिवसीय चिंतन शिविर का प्रारंभ कराया

▶▶ कोलोबरेट, इनोवेट एंड ट्रांसफॉर्म फॉर बेटर लैंड गवर्नेंस थीम के साथ राजस्व अधिकारियों-जिला कलेक्टरों का सामूहिक चिंतन-मंथन

▶▶ चिंतन शिविर स्वयं के साथ संवाद तथा छोटे से छोटे व्यक्ति के सुख-समृद्धि एवं कल्याण के चिंतन का सक्षम माध्यम है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▶▶ पूज्य श्री दीपकभाई देसाई ने राजस्व अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रेरणादायी प्रवचन से प्रोत्साहित किया

▶▶ प्रशासनिक प्रक्रिया को नागरिकों की सेवा मानकर जन समस्याओं को हल करना राज्य सरकार की प्राथमिकता : राजस्व राज्य मंत्री श्री संजयसिंह महीडा

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को राज्य सरकार के राजस्व विभाग के तीन दिवसीय चिंतन शिविर का प्रारंभ कराते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि चिंतन शिविर स्वयं के साथ संवाद एवं छोटे से छोटे व्यक्ति के सुख-समृद्धि एवं कल्याण के चिंतन का सक्षम माध्यम है।

इस संदर्भ में श्री पटेल ने कहा कि राज्य सरकार के महत्वपूर्ण राजस्व विभाग और जिलों के प्रशासनिक प्रमुखों के रूप में कलेक्टरों की सामूहिक शक्ति से सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए कार्यमंत्र को हम गुजरात में सफलतापूर्वक साकार करें।

राजस्व विभाग द्वारा अडालज स्थित त्रिमंदिर परिसर में यह तीन दिवसीय चिंतन शिविर कोलोबरेट, इनोवेट एंड ट्रांसफॉर्म फॉर बेटर लैंड गवर्नेंस की विषय वस्तु (थीम) के साथ आयोजित हो रहा है। राज्य के जिला कलेक्टर तथा राजस्व विभाग के अधिकारी इस चिंतन शिविर में सहभागी हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सदैव लोगों की सुख-सुविधा तथा लोकहित के कार्य करने की व्यवस्थाएँ विकसित कर देश का गौरव बढ़ाया है।

उन्होंने जोड़ा कि कलेक्टरों के पास विशाल अधिकार हैं और हम लोक कल्याण के कार्यों के लिए ही बैठे हैं, तब चिंतामुक्त रहकर स्पष्टता एवं संवेदना के साथ समस्याओं का हल हो; यही हमारा दायित्व होना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राजस्व अधिकारियों को उनके पास आने वाले लोगों को कोई हिचक न रहे तथा संतोष की अनुभूति हो; ऐसा आचरण-व्यवहार हँसते चेहरे से करने की भी सीख दी। इस संबंध नें श्री पटेल ने दादा भगवान के बोध को उद्धृत करते हुए कहा कि दुनिया किस प्रकार चलती है; यह समझ हमें विकसित करनी होगी और सब मैं ही करता हूँ; यह आत्ममुग्धता भाव त्यागकर सबको साथ मिलकर काम करने के रुख से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है।

मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास में राजस्व विभाग तथा जिला कलेक्टरों के योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए जीरो टोलरेंस की दिशा में सब साथ मिलकर सामूहिक चिंतन-मंथन से कार्यरत रहें।

मुख्यमंत्री ने शिविरार्थियों का प्रेरक आह्वान किया कि वे विकसित भारत-2047 के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए संकल्प को विकसित गुजरात से साकार करने के लिए पूर्णतः कार्यनिष्ठा एवं जनसेवा की प्रतिबद्धता के साथ सेवारत रहें। चिंतन शिविर के शुभारंभ अवसर पर पूज्य श्री दीपकभाई देसाई ने राज्य सरकार के राजस्व अधिकारियों-कर्मचारियों को कर्म एवं सेवा के साथ अध्यात्म को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने वाला प्रेरणादायी प्रवचन किया।

अध्यात्म, व्यवहार तथा आचार-विचार के विषय में पूज्य श्री दीपकभाई ने अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि कर्म के सिद्धांतों तथा उसके उद्देश्य को जानकर दादा भगवान द्वारा दिए गए विचारों जैसे कि चोरी न करना, सेवा भक्ति के मार्ग पर चलना, परोपकार करना, दान करना, शुद्ध आचरण, कर्म को समझना, स्व-कर्म को समझकर व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करना तथा धर्म एवं संस्कार से युक्त मार्ग पर चलना अत्यंत ही आवश्यक है। उन्होंने सामान्य जीवन में महत्व रखने वाले आर्थिक व्यवहार-लेन-देन के बारे में नीति से लक्ष्मी प्राप्त करने, माता-पिता के साथ सद्व्यवहार, किसी को भी लेशमात्र हानि या दुःख न पहुँचाने वाला व्यवहार करने तथा क्रोध, लोभ माया से मुक्त होने और पूर्व जन्म के कर्म एवं जन्म-मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के उद्देश्य के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▶▶ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सदैव लोगों के सुख-समृद्धि एवं कल्याण तथा लोकहित कार्यों से देश का गौरव बढ़ाया है

▶▶ हम जनोन्मुखी कार्य करने ही बैठे हैं, तब चिंतामुक्त होकर स्पष्टता एवं संवेदना के साथ कार्यरत रहें

▶▶ सामूहिक शक्ति से सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के प्रधानमंत्री के कार्यमंत्र को 'विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात' से साकार करें

राजस्व राज्य मंत्री श्री संजयसिंह महीडा ने कहा कि प्रशासनिक प्रक्रिया को नागरिकों की सेवा मानकर सुदूरवर्ती व्यक्ति की समस्याएँ हल करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। गुजरात सरकार ने आईओआरए तथा ई-धरा जैसे माध्यमों द्वारा फेसलेस एवं पेपरलेस गवर्नेंस अपनाकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया है। उद्योगों एवं सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन में जीरो डीले की नीति तथा पारदर्शी प्रशासन के कारण गुजरात आज वैश्विक निवेशकों के लिए पसंदीदा राज्य बना है।

उन्होंने आगे कहा कि पूर्व में री-सर्वे में हुई क्षतियाँ सुधारने के लिए अब ड्रोन टेक्नोलॉजी तथा सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग किया जा रहा है। 135-डी के नोटिस, उत्तराधिकार तथा अधिकार पत्रक की प्रक्रियाओं को और सरल तथा तेज बनाया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जीरो टोलरेंस नीति के विजन के साथ भूमि रिकॉड्र्स का रियल टाइम अपडेट और पूर्णतः डिजिटलाइजेशन कर पुराने कानूनों में आधुनिक सुधारों से गुजरात को अधिक उन्नत बनाया गया है।

मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार दास ने राजस्व प्रशासन के कार्य की प्रशंसा करते हुए विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए टेक्नोलॉजी तथा पारदर्शिता अपनाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में राजस्व विभाग ने विकास परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन कार्य में रिकॉर्डब्रेक प्रदर्शन किया है। विशेषकर रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी तथा सोलर सेक्टर में गुजरात आज देश में अग्रसर है और इसके मूल में राजस्व विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है। श्री दास ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए जिलों में अपर कलेक्टरों की नई रिक्तियाँ मंजूर की हैं। इसके अलावा राजस्व प्रशासन के आधारभूत ढाँचे को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पटवारी एवं सर्वेयर की नई भर्ती भी की गई है।

राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि ने चिंतन शिविर के समग्र आयोजन की विस्तृत भूमिका देते हुए कहा कि प्रशासन में केवल लॉजिक या विज्ञान ही नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन एवं आध्यात्मिक ऊर्जा का समन्वय भी अनिवार्य है। दादा भगवान के सान्निध्य में यह शिविर आयोजित करने का उद्देश्य यही है कि अधिकारी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ अपने कर्तव्य को एक 'योग' समझकर काम करें, जिससे किसी भी चुनौती के बीच भी काम करने की अपार शक्ति प्राप्त हो।

भारत में कलेक्टर संस्थान के 254 वर्षों के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आज भी जनमानस में कलेक्टर की एक विशिष्ट पहचान है। नए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में यह चिंतन शिविर आयोजित करने के पीछे कारण प्रशासन में अधिक सटीकता एवं पारदर्शिता लाना है। यह शिविर केवल चर्चा तक सीमित न रहते हुए राजस्व विभाग में एक गुणात्मक परिवर्तन लाएगा, जिसका सीधा लाभ राज्य के नागरिकों को मिलेगा।

शिविर के आरंभ में राज्य के सैटलमेंट आयुक्त श्री बीजल शाह ने सभी का स्वागत करते हुए शिविर के दौरान आयोजित होने वाले विभिन्न सत्रों एवं गतिविधियों का विवरण दिया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, राहत आयुक्त एवं सचिव श्री आलोक कुमार पांडे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य श्री दिनेश कुमार असवाल, गांधीनगर जिला कलेक्टर श्री रविन्द्र खटाले सहित जिला कलेक्टर, राजस्व अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित रहे।

अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन, भावनगर मंडल द्वारा रेल कर्मचारियों का सम्मान

अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन, भावनगर मंडल द्वारा दिनांक 05 मई, 2026 (मंगलवार) को ऑफिसर क्लब, भावनगर परा में रेल कर्मचारियों के सम्मान हेतु एक गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ संगठन की अध्यक्षा श्रीमती शालिनी वर्मा द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने मंडल के 50 उत्कृष्ट कर्मचारियों को उपहार भेंट कर सम्मानित किया।

अपने संबोधन में श्रीमती वर्मा ने कहा कि रेलवे के कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में भी पूर्ण समर्पण एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ रेलगाड़ियों का संचालन सुनिश्चित करते हैं, जो अत्यंत प्रशंसनीय है। उन्होंने कर्मचारियों के योगदान को संगठन की सफलता का आधार बताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

कार्यक्रम के दौरान सम्मानित कर्मचारियों ने भी अपने सेवा अनुभव साझा किए, जिससे वातावरण प्रेरणादायक एवं उत्साहवर्धक बन गया।

इस अवसर पर पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन, भावनगर मंडल की सचिव, कोषाध्यक्ष सहित अन्य सदस्यगण भी उपस्थित रहे।

ओवरटेक की एक चूक बनी काल: नूंह एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे में यूपी पुलिस के चार जवान समेत पांच की मौत

हरियाणा के नूंह जिले में कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह जो हुआ, उसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सड़क पर एक छोटी सी चूक किस तरह कई जिंदगियों को लील सकती है। यह कोई साधारण हादसा नहीं था, बल्कि तेज रफ्तार, असावधानी और एक क्षणिक निर्णय का ऐसा घातक परिणाम था, जिसने पांच परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। इस भीषण दुर्घटना में उत्तर प्रदेश पुलिस के चार जवानों सहित कुल पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी पुलिसकर्मी उरई में तैनात थे, जिससे पूरे जालौन जिले में शोक और सन्नाटा छा गया है। सुबह का समय था, जब काले रंग की स्कॉर्पियो एक्सप्रेसवे पर तेज गति से पलवल की दिशा में बढ़ रही थी। सड़क लगभग साफ थी और वाहन की रफ्तार भी काफी अधिक बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जैसे ही वाहन तावड़ू क्षेत्र के धुलावट टोल प्लाजा के पास पहुंचा, चालक ने आगे चल रहे वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश की। लेकिन यही वह क्षण था, जहां एक गलत अनुमान और तेज गति ने मिलकर हादसे को जन्म दे दिया। ओवरटेक करते समय चालक संतुलन खो बैठा और सामने से आ रहे वाहन से सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और अंदर बैठे लोग लोहे के ढांचे में बुरी तरह फंस गए। घटनास्थल का दृश्य इतना भयावह था कि आसपास मौजूद लोग भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कुछ ही सेकंड में क्या हो गया। राहगीरों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन शवों को निकालना आसान नहीं था। वाहन की हालत ऐसी थी कि उसे काटकर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालना पड़ा। इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगा और हर गुजरता मिनट वहां मौजूद लोगों के लिए भारी पड़ रहा था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, हादसा इतना गंभीर था कि किसी भी सवार के बचने की कोई संभावना नहीं रही। घटनास्थल से मिले पहचान पत्रों के आधार पर मृतकों की पहचान की गई। चारों पुलिसकर्मी—एएसआई मोहित यादव, सत्यभान, अशोक और प्रदीप—जालौन जिले के उरई मुख्यालय में तैनात थे। पांचवें मृतक की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है, जिसके लिए पुलिस जांच कर रही है। यह भी सामने आया है कि सभी लोग हरियाणा नंबर की एक नई स्कॉर्पियो में सवार थे, जो जींद आरटीओ में पंजीकृत थी। हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया और मृतकों के परिजनों को सूचना दी गई। जैसे ही यह खबर उरई और जालौन पहुंची, वहां शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस विभाग में भी मातम का माहौल है, क्योंकि एक ही घटना में चार जवानों को खोना बेहद बड़ा आघात है। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हो रहा है कि तेज रफ्तार इस दुर्घटना का मुख्य कारण रही। एक्सप्रेसवे पर अक्सर वाहन चालक गति सीमा का उल्लंघन करते हैं और ओवरटेक करते समय पर्याप्त सावधानी नहीं बरतते। यही लापरवाही कई बार ऐसे घातक हादसों का कारण बनती है। इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

भारत की धर्मनिरपेक्षता, राजनीति की वास्तविकता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की आवश्यकता

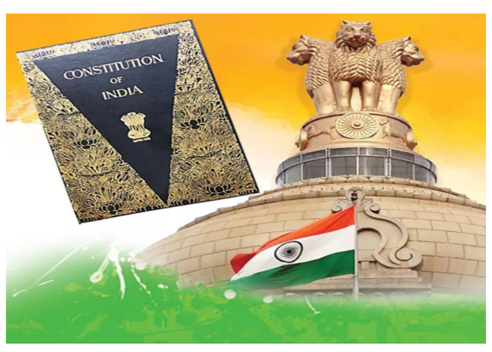

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। हमारे देश की सच्चाई यह है कि भारत का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष है और देश के सभी नागरिकों को संविधान का पालन करना चाहिए जो इस संस्कृति की रक्षा करता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर भारत को एकजुट करने और संविधान की रक्षा करने के आंदोलन में शामिल हों और नकारात्मक तत्वों को करारा जवाब देकर सच्ची भाईचारे की भावना का संदेश दें।

कुछ समय पहले कांग्रेस के राजनीतिक अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे ने आपा खोकर गुजरात के लोगों को अनपढ़ और मूर्ख कहा था। हाल ही में स्वायत्त निकायों के चुनावों के नतीजों से परेशान होकर गुजरात भाजपा के अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने आपा खो दिया और कांग्रेस की लोकप्रिय महिला सांसद श्रीमती जेनीबेन ठाकोर का सार्वजनिक रूप से अपमान किया। हमारे लोकतांत्रिक देश में चुनावों में जीत और हार होना स्वाभाविक है। लेकिन इस पर किसी को भी आपा नहीं खोना चाहिए।

राजनीति में शामिल व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में कैसा होना चाहिए? यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसका जीवन खुली किताब की तरह होना चाहिए। इसके विपरीत, आजकल कुछ बेरोजगार और निकम्मे लोग चुनाव के दौरान ब्लैकमेल करके पैसे वसूलने के लिए अपनी "दुकानें" खोल लेते हैं। क्या किसी खास समुदाय को निशाना बनाकर बेमतलब और बढ़ा-चढ़ाकर भाषण देने वाले लोग कभी नगर पालिका या नगर परिषद जीत सकते हैं? क्या वे सरकार बनाने के लिए जरूरी विधायक या सांसद चुन सकते हैं? ऐसे अदूरदर्शी और निकम्मे लोगों की वजह से आज चुनाव एक चटनी बन गए हैं। और वे जो भी मिलता है उसे चाटने बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसी चटनी का स्वाद उतना स्वादिष्ट नहीं होता जितना होना चाहिए। जो जनता (मतदाताओं) को कभी पसंद नहीं आएगा।

यह देश धर्मनिरपेक्ष है और जब भी धर्मनिरपेक्ष सरकारें सत्ता में आईं, उनका लाभ, विशेष रूप से ईसाई, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी और दबे-कुचले वर्गों जैसे विभिन्न धर्मों के लोगों को मिला। देश में नफरत भरे भाषण नहीं हुए। किसी पर भी अदालत या पुलिस में गलत मुकदमा नहीं चलाया गया, लोगों को बोलने, लिखने और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने का अधिकार था, जिसमें आंदोलन भी शामिल थे। धर्मनिरपेक्ष सरकारों ने इन अधिकारों का बखूबी पालन किया और लोकतंत्र को जीवित रखा। क्या आज की नकारात्मक राजनीति देश को डुबा देगी?

मानसून से पहले राजकोट में अलर्ट मोड : हर तालुका में विशेष तैनाती, आपदा प्रबंधन को लेकर व्यापक तैयारी

राजकोट। गुजरात के राजकोट जिले में आगामी मानसून को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। संभावित भारी बारिश, बाढ़ और अन्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पहले से ही रणनीतिक योजना तैयार कर ली है, ताकि किसी भी तरह की जनहानि और नुकसान को न्यूनतम किया जा सके। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि आपदा प्रबंधन योजना को केवल कागजों तक सीमित न रखकर उसे जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिले के प्रत्येक तालुका में एक डिप्टी कलेक्टर सहित कुल 12 अधिकारियों की विशेष तैनाती की जाएगी। इन अधिकारियों को मानसून के दौरान आने वाली किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने और स्थानीय स्तर पर राहत एवं बचाव कार्यों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रशासन का मानना है कि स्थानीय स्तर पर त्वरित निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने से आपदा के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जिला विकास अधिकारी आनंदू सुरेश गोविंद की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मानसून से पहले आवश्यक तैयारियां पूरी कर लें। उन्होंने खास तौर पर जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने पर जोर दिया। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां-जहां पानी भरने की समस्या पहले सामने आई है, उन स्थानों का सर्वे कर स्थायी समाधान निकालने के निर्देश दिए गए।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि जल प्रवाह में बाधा डालने वाले किसी भी अवरोध को तुरंत हटाया जाए। नालों, नहरों और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है, ताकि बारिश के दौरान पानी का बहाव बाधित न हो। इसके साथ ही, संभावित जलभराव वाले क्षेत्रों की पहचान कर वहां पहले से ही चेतावनी और सुरक्षा उपाय लागू किए जा रहे हैं।

रेजिडेंट अतिरिक्त कलेक्टर एन.के. मुछारे ने बिजली विभाग और नगर निकायों को निर्देश दिए कि जर्जर बिजली के खंभों, ढीले तारों और ऊंची इमारतों पर लगे खतरनाक होर्डिंग्स को समय रहते हटाया जाए। उनका कहना था कि मानसून के दौरान तेज हवाओं और बारिश के कारण ये ढांचे गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं।

बैठक में जनहानि रोकने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में राहत कार्यों में देरी न हो। पोस्टमॉर्टम और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को शीघ्रता से पूरा कर प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि संकट की घड़ी में उन्हें राहत मिल सके। इसके अलावा, पंचायत, निर्माण, स्वास्थ्य, कृषि और पशुपालन विभागों को अपने कर्मचारियों के साथ विशेष बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सभी स्तरों पर जागरूकता और तैयारी सुनिश्चित की जा सके। किसानों को फसल सुरक्षा के उपायों के बारे में जानकारी दी जा रही है, वहीं पशुपालन विभाग को पशुओं के लिए सुरक्षित स्थान और चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

प्रशासन ने 1 जून से प्रत्येक तालुका स्तर पर 24 घंटे सक्रिय रहने वाले फ्लड कंट्रोल रूम शुरू करने का निर्णय लिया है। इन कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार स्थिति की निगरानी की जाएगी और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जाएगी। संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी विशेष कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि सूचना का आदान-प्रदान तेजी से हो सके।

निचले इलाकों की पहचान कर वहां रहने वाले लोगों के लिए सुरक्षित स्थानों की सूची तैयार की जा रही है। साथ ही, तैराकों और बचाव उपकरणों की पहले से ही व्यवस्था की जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत राहत कार्य शुरू किया जा सके। प्रशासन ने संबंधित विभागों को बांधों और नहरों का नियमित निरीक्षण करने और नदी तल की सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।

इसके साथ ही, जर्जर इमारतों पर चेतावनी बोर्ड लगाने और आवश्यक होने पर उन्हें खाली कराने की योजना भी बनाई गई है। सरकारी गोदामों में रखे अनाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि बारिश के दौरान किसी भी प्रकार का नुकसान न हो।

बैठक में डीसीएफ बहादुरसिंह मीणा, डीआरडीए निदेशक ए.के. वस्तानी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, प्रांतीय अधिकारी, ममलतदार, तालुका विकास अधिकारी और नगर निगमों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर इस बात पर सहमति जताई कि मानसून के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

कुल मिलाकर, राजकोट प्रशासन ने इस बार मानसून को लेकर पहले से कहीं अधिक गंभीरता और सतर्कता दिखाई है। यह तैयारी न केवल संभावित आपदाओं से निपटने में मदद करेगी, बल्कि आम जनता के बीच भी सुरक्षा और भरोसे का माहौल बनाएगी।

क्रूड ऑयल वायदा 146 रुपये फिसला: सोना वायदा में 458 रुपये और चांदी वायदा में 1417 रुपये की वृद्धि

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 117369.31 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 20992.12 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 96376.98 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का मई वायदा 36014 पॉइंट के स्तर पर ट्रेड हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2395.94 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 13246.78 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा 149749 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 149996 रुपये और नीचे में 149228 रुपये पर पहुंचकर, 149339 रुपये के पिछले बंद के सामने 458 रुपये या 0.31 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 149797 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-गिनी मई वायदा 251 रुपये या 0.21 फीसदी की बढ़त के साथ 120840 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-पेटल मई वायदा 32 रुपये या 0.21 फीसदी की तेजी के संग 15145 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर पहुंचा। सोना-मिनी मई वायदा 147361 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 147743 रुपये और नीचे में 147090 रुपये पर पहुंचकर, 429 रुपये या 0.29 फीसदी की तेजी के संग 147475 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-टेन मई वायदा प्रति 10 ग्राम 149861 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 150290 रुपये और नीचे में 149482 रुपये पर पहुंचकर, 149719 रुपये के पिछले बंद के सामने 345 रुपये या 0.23 फीसदी की तेजी के संग 150064 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा।

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा 238381 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 240800 रुपये और नीचे में 236001 रुपये पर पहुंचकर, 239383 रुपये के पिछले बंद के सामने 1417 रुपये या 0.59 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 240800 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इनके अलावा चांदी-मिनी जून वायदा 1834 रुपये या 0.74 फीसदी की बढ़त के साथ 249440 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो जून वायदा 1803 रुपये या 0.73 फीसदी की मजबूती के साथ 249478 रुपये प्रति किलो बोला गया।

मेटल वर्ग में 1969.50 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मई वायदा 8.75 रुपये या 0.69 फीसदी बढ़कर 1285.5 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता मई वायदा 2.65 रुपये या 0.77 फीसदी बढ़कर 345.1 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम मई वायदा 2.5 रुपये या 0.67 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 373.5 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा मई वायदा 60 पैसे या 0.3 फीसदी चढ़कर 200.2 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

▶▶ कमोडिटी वायदाओं में 20992.12 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 96376.98 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 13246.78 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 36014 पॉइंट के स्तर पर

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 5774.38 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मई वायदा 9960 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 10066 रुपये और नीचे में 9840 रुपये पर पहुंचकर, 146 रुपये या 1.45 फीसदी गिरकर 9911 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मई वायदा 149 रुपये या 1.48 फीसदी गिरकर 9912 रुपये प्रति बैरल हुआ। इनके अलावा नैचुरल गैस मई वायदा सत्र के आरंभ में 272 रुपये के भाव पर खूलकर, 273.7 रुपये के दिन के उच्च और 269.4 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 274.5 रुपये के पिछले बंद के सामने 3.6 रुपये या 1.31 फीसदी गिरकर 270.9 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मई वायदा 3.7 रुपये या 1.35 फीसदी लुढ़ककर 270.9 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मई वायदा 982.2 रुपये पर खूलकर, 1.2 रुपये या 0.12 फीसदी औंधकर 986 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 8405.81 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 4840.97 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 1428.84 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 255.41 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 8.74 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 268.40 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 4149.85 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1598.75 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 1.03 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 11510 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 68588 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 27813 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 379644 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 59876 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 8140 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 23350 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 82355 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 21202 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 25545 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स मई वायदा 35942 पॉइंट पर खूलकर, 36014 के उच्च और 35942 के नीचले स्तर को छूकर, 189 पॉइंट बढ़कर 36014 पॉइंट के स्तर पर ट्रेड हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल मई 10000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 99.5 रुपये की गिरावट के साथ 586.6 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मई 270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.6 रुपये की गिरावट के साथ 13.85 रुपये हुआ। सोना मई 170000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 20 रुपये की बढ़त के साथ 222 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मई 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 11.5 रुपये की गिरावट के साथ 591 रुपये हुआ। तांबा मई 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.73 रुपये की बढ़त के साथ 19.19 रुपये हुआ। जस्ता मई 345 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 65 पैसे के सुधार के साथ 4.4 रुपये हुआ। पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल मई 9000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 14 रुपये की बढ़त के साथ 247 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मई 270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.05 रुपये की बढ़त के साथ 12.15 रुपये हुआ। सोना मई 140000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 80 रुपये की गिरावट के साथ 644 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मई 220000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 311.5 रुपये की गिरावट के साथ 2012 रुपये हुआ। तांबा मई 1250 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 2.03 रुपये की गिरावट के साथ 12.9 रुपये हुआ। जस्ता मई 342.5 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 71 पैसे के सुधार के साथ 5.64 रुपये हुआ।